नववर्ष की शुभकामनाएं

खंड १८ नंबर १ जनवरी २०२२

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

डब्लयूटीडीआर

विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 का लोकार्पण

25 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट का लोकार्पण

आरआईएस ने विश्व व्यापार संगठन (डबलूटीओ) के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सन्मुखः मुद्दे विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट के विमोचन पर 25 नवंबर 2021 को एक कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुआ। आरआईएस के अध्यक्ष, डॉ मोहन कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री श्यामल मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया।

आरआईएस के प्रोफेसर एस के मोहंती, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ प्रियदर्शी दाश और सहायक प्रोफेसर, डॉ पंखुरी गौर ने डब्लयूटीडीआर के प्रमुख निष्कर्षों पर प्रस्तुति की। उसके बाद परिचर्चा में, श्री जयंत दासगुप्ता, विश्व व्यापार संगठन के पूर्व राजदूत; श्री अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच; प्रोफेसर अभिजीत दास, प्रमुख, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र, आईआईएफटी; और डॉ. निशा तनेजा, प्रोफेसर, आईसीआरआईईआर ने अपने विचार साझा किए। डॉ सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

श्रीमती मीनाक्षी लेखी, माननीया विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, भारत

माननीया विदेश राज्य मंत्री ने आरआईएस के कार्यक्रम की सराहना की और गहन नीतिगत जुड़ाव का आह्वान किया

भारत की माननीया विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आरआईएस के कार्यक्रम के संदर्भ में संकाय के सदस्यों के साथ एक संवाद सत्र के लिए 30 दिसंबर, 2021 को आरआईएस में पधारी। गहन संवाद सत्र के दौरान, आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने माननीया मंत्री को संस्थान के इतिहास और संगठनात्मक संरचना, महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों, अनुसंधान

...शेष पृष्ठ 28 पर

एमसी–12 के स्थगन से अधिक काम की गुंजाइश बढ़ी

विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट (डब्लयू) 2021 के उद्भघाटन के बाद 27 नवंबर, 2021 को आरआईएस द्वारा आयोजित एक वेबिनार में प्रमुख वक्ता।

आर आई एस द्वारा प्रकाशित विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के उद्घाटन के बाद 27 नवंबर, 2021 को आरआईएस ने एक वेबिनार का आयोजन किया।

ओमीक्रोन के प्रसार के कारण, वेबिनार शुरू होने से पहले ही एमसी–12 को स्थगित करने की घोषणा की खबर आ चुकी थी। लेकिन वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के स्थगन का उपयोग भारत को दक्षिण के साथ जुड़ने के लिए करना चाहिए। वैश्विक दक्षिण के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी–12) के स्थगन के प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए और इसके फिर से आयोजित होने तक के समय का अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट रहने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उपयोग करना चाहिए। एमसी–12 (30 नवंबर – 3 दिसंबर, 2021 के लिए निर्धारित) को स्थगित करने का निर्णय विश्व व्यापार संगठन सामान्य परिषद द्वारा कोविड–19 वायरस के एक विशेष रूप से संक्रमणीय स्ट्रेन के प्रकोप के बाद लिया गया था।

वेबिनार में बोलते हुए, प्रोफेसर कार्लोस कोरिया, कार्यकारी निदेशक, दक्षिण केंद्र, जिनेवा, ने कहा कि दक्षिण केंद्र और आरआईएस जैसे विकासशील देशों के विचार मंडलों को सभी प्रस्तावों का विश्लेषण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमसी12 के स्थगन से मत्स्य पालन सब्सिडी, कृषि, ट्रिप्स छूट और विशेष तथा विभेदी व्यवहार सहित विभिन्न मुद्दों पर विकासशील देश की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

प्रौद्योगिकी और व्यापार एक–दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस बात को डब्लूटीडीआर द्वारा कितना महत्व दिया जा रहा है का उल्लेख करते हुए प्रो कौरिया ने कहा कि इस मुद्दे को, जो हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है, विशेष रूप से कोविड पश्चात के परिदृश्य में जिस प्रकार डिजिटलीकरण में तेजी देखी गई, ।

आरआईएस के अध्यक्ष, डॉ मोहन कुमार ने कहा कि विकासशील देशों को एमसी–12 के स्थगित होने के कारण सामने आए अवसरों और चुनौतियों को देखते हुए एक साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'किसी भी कीमत पर एमसी–12 की सफलता' सुनिश्चित करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि 'सफलता' पर केवल विकसित दुनिया का कब्जा हो जाए और विकासशील देश मात्र इसकी कीमत चुकाने के लिए रह जाएं।

विश्व व्यापार संगठन में भारत के पूर्व राजदूत श्री जयंत दासगुप्ता ने कहा कि एमसी–12 को स्थगित करने से विकासशील देशों को ऐसे प्रस्तावों के विरुद्ध, जो उनके हितों के खिलाफ हैं, मजबूती से अपनी बात रखने के लिए तैयार होने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को सतत्ता और जातीयता जैसे मुद्दों पर सफाई देनी होगी जिनके माध्यम से वे परोक्ष रूप से विकासशील देशों के बाजार में पहुंच हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

डॉ नागेश कुमार, निदेशक, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, ने भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा ट्रिप्स छूट पर प्रस्ताव के महत्व का उल्लेख किया और कहा कि विश्व व्यापार संगठन को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि विकासशील देशों में अरबों गरीब लोगों के जीवन की सुरक्षा कोविड वैक्सीन, डायग्नोस्टिक किट और दवाइयाँ विकसित करने वाली कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निचली पंक्ति की सुरक्षा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए निवेश सुविधा पर चर्चा से निवेशकों, अपने देश और मेजबान देश के अधिकारों और जिम्मेदारियों में संतुलन सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे प्रमुख विकासशील देशों को निवेश सुविधा सहित बहुपक्षीय देशों का हिस्सा होना चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनका परिणाम विकासशील देशों के हितों के खिलाफ नहीं है।

आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, ने कहा कि विकासशील देशों के गठबंधनों को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण है

...शेष पृष्ठ 9 पर

जी 20

टी–20 में विकासशील देशों से अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए

दुनिया भर के शोधकर्ताओं के अनुसार, थिंक20 में, जो 20 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं वाले जी20 समूह से जुड़े महत्वपूर्ण जुड़ाव समूहों में से एक है, विकासशील देशों के विचार मंडलों से अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उसे वैश्विक शासन से सम्बन्धित मुद्दों पर अपनी नीतिगत सिफारिशें समय पर प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि जी20 के नेता उनका विश्लेषण कर सकें और उन्हें अपनी अंतिम घोषणा में शामिल कर सकें। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमुख विकासशील देश इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः 2022, 2023, 2024 और 2025 में जी20 की अध्यक्षता करने वाले हैं। अपेक्षा की जा जाती है कि विकास का एजेंडा जी20 और इसके जुड़ाव समूहों – बिजनेस 20, थिंक 20, वूमेन 20, यूथ 20, लेबर 20, अर्बन 20, सिविल 20 और साइंस 20 – द्वारा होने वाली चर्चाओं में सबसे पहले और केंद्र में रहेगा। प्रक्रियाओं को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और उनके द्वारा आवाज उठाए जाने की मांग की जा रही है।

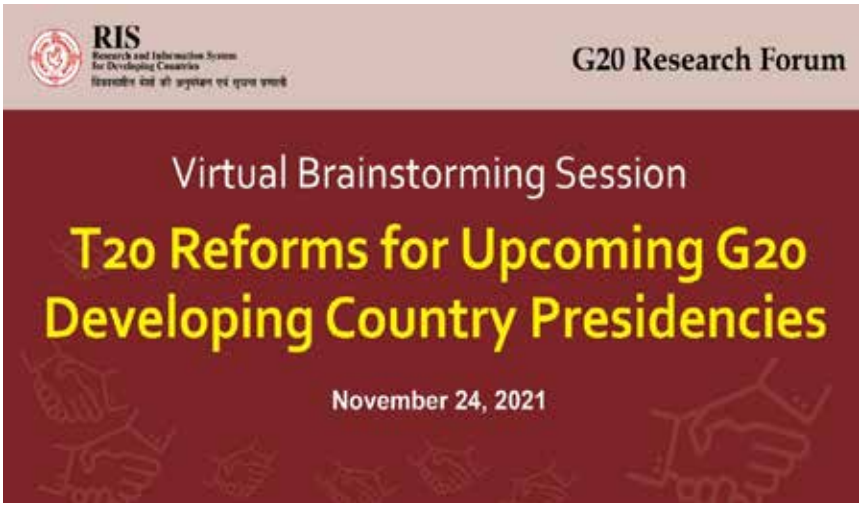

24 नवंबर, 2021 को आरआईएस द्वारा आयोजित 'आगामी जी20 की विकासशील देशों द्वारा अध्यक्षताके लिए टी20 सुधार' पर एक हुए वबीनार के सत्र में बोलते हुए, टी20 इंडोनेशिया के प्रमुख सह–अध्यक्ष और इंडोनेशिया के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर बंबांग ब्रोडजोनगोरो ने कहा कि इंडोनेशिया सभी महाद्वीपों और सभी आय समूहों के देशों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अवसंरचना वित्तपोषण, एसडीजी, डिजिटलीकरण और बहुपक्षवाद के पुनरुद्धार जैसे मुद्दों का विकासशील और विकसित देशों के लिए बहुत महत्व है। इसलिए इन मुद्दों को जी20 सदस्यों द्वारा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए टी20 प्रक्रिया में निरंतरता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की जी20 अध्यक्षता के दौरान गरीबी और आय असमानता के साथ–साथ सतत विकास एजेंडा के सतत वित्तपोषण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।

टी20 इंडोनेशिया के प्रमुख सह–अध्यक्ष, प्रो जिस्मान सिमंदजुंतक, ने कहा कि नवीन नीतिगत विचार प्राप्त करने की दृष्टि से इंडोनेशिया अफ्रीकी विचार–मंडलों से संपर्क करेगा और अन्य शोधकर्ताओं के नीतिगत संक्षिप्त विवरण पर भी विचार करेगा, जिन्हें अब तक टी20 प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला है। दक्षिण अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों का संस्थान, दक्षिण अफ्रीका की मुख्य कार्यकारी सुश्री एलिजाबेथ सिदिरोपोलोस ने 'टी20 अफ्रीका स्टैंडिंग ग्रुप' को एक महत्वपूर्ण वार्ताकार और अब से टी20 प्रक्रिया का हिस्सा बताया। सुश्री अनीता प्रकाश, वरिष्ठ नीति सलाहकार (अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध), इरिया, जकार्ता ने प्रतिभागियों को इरिया, आरआईएस और इंडोनेशिया के 'एलवामफब आईयू' द्वारा नए शुरू किए गए जी20 शोध मंच के बारे में जानकारी दी, ताकि वैश्विक शासन के मुद्दों पर विभिन्न थिंक–टैंक और शोधकर्ताओं के विचारों का मिलान किया जा सके। जर्मनी विकास संस्थान, जर्मनी के उप निदेशक, डॉ इममे स्कोल्ज़, ने टी –20 जर्मनी के आयोजन के तरीकों का उल्लेख किया जिसमें इंडोनेशिया और भारत के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जर्मनी 2022 में जी7 की अध्यक्षता करने जा रहा है और विभिन्न मुद्दों पर इंडोनेशिया (2022 के लिए जी20 प्रेसीडेंसी) के साथ घनिष्ठ सहयोग के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जी7–जी20 और उनसे जुड़े जुड़ाव समूहों का समन्वय तंत्र सभी जी20 आयोजनों पर लागू किया जाना चाहिए।

सत्र में अन्य प्रमुख वक्ता थेः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; प्रोफेसर नाओयुकी योशिनो, प्रोफेसर अवकाशप्राप्त (अर्थशास्त्र), कीओ विश्वविद्यालय, जापान; सुश्री गाला डियाज़ लेंगौ, कार्यकारी निदेशक, सीआईपीपीईसी, अर्जेंटीना; डॉ एंटोनियो विलाफ्रांका, अनुसंधान निदेशक, इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज, इटली; डॉ रियातु मरियातुल किबथियाह, निदेशक, एलपीईएम, इंडोनेशिया विश्वविद्यालय; डॉ योस रिज़ल दामुरी, प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, जकार्ता; डॉ निकोलस बुकौड, ग्रैंड एलायंस, पेरिस; डॉ प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस और श्री ऑगस्टीन पीटर, विजिटिंग फेलो, आरआईएस। ■

बहुपक्षीय संस्थाओं का सुधार

राजदूत संजय भट्टाचार्य, सचिव (सीपीवी और ओआईए), विदेश मंत्रालय और भारत के ब्रिक्स शेरपा 26 नवंबर, 2021 को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से आरआईएस द्वारा आयोजित 'ब्रिक्स आभासी आर्थिक सम्मेलन 2021' में भाग लिया।

ब्रिक्स को बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के प्रयासों को मजबूत करने की जरूरत

राजदूत संजय भट्टाचार्य, सचिव (सीपीवी और ओआईए), विदेश मंत्रालय और भारत के ब्रिक्स शेरपा के अनुसार, ब्रिक्स देश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के साथ–साथ, आतंकवाद का मुकाबला, हरित और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अलावा संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने और सुधारने के अपने प्रयास जारी रखने होंगे।

26 नवंबर, 2021 को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से आरआईएस द्वारा आयोजित 'ब्रिक्स आभासी आर्थिक सम्मेलन 2021' में बोलते हुए, राजदूत भट्टाचार्य ने कहा कि ब्रिक्स जुड़ाव के तीन स्तंभ हैं; ब्रिक्स के भीतर और बहुपक्षीय स्तर पर संरचनाओं का 'सुधार'; ब्रिक्स देशों ने अब तक जो काम किया है, उसका 'समेकन'; और एसटीआई के माध्यम से भविष्य अभिविन्यास और साथ ही साथ, पहुंच, साम्य और समावेशन के सिद्धांत के आधार पर 'हरित और डिजिटल' परिवर्तन सुनिश्चित करना। उन्होंने यह भी जोर दिया कि 'पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं आतंकवाद के विरोध, 'हरित और डिजिटल' परिवर्तन, और एसटीआई पर भी सहयोग बढ़ाएंगी।'

उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि 'शांति और स्थिरता विकास का आधार बनती है। संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ सहित बहुपक्षीय संस्थानों के सुधारों की मांग के पीछे कारण यह है कि मौजूदा प्रणाली वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने में असमर्थ है, विशेष रूप से विकासशील दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में। चूंकि ब्रिक्स देश दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से हैं, इसलिए इन पांच देशों द्वारा उठाए गए कदम दुनिया के बाकी हिस्सों और विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के अनुसरण के लिए एक खाका तैयार कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ने वैश्विक संकट से उबरने और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने आपूर्ति पक्ष के संघर्षों से प्रभावी ढंग से निपटते हुए सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था बहाली के लिए आपूर्ति पक्ष के झटकों का अध्ययन किया और उनका निवारण किया। इस प्रक्रिया में, भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में लचीला और संधारणीय सामाजिक अवसंरचना सहित उत्पादक परिसंपत्ति बनाने के लिए पूंजीगत व्यय पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि

...शेष पृष्ठ 17 पर

एसटीआईपी

38वां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति मंच व्याख्यान

38वां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति मंच व्याख्यान, प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी, निदेशक, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल, उत्तराखंड ने 29 अक्टूबर, 2021 को ऑनलाइन माध्यम से दिया। विषय था 'भारत में जमीन और अंतरिक्ष आधारित मंचों से सौर भौतिकी का विकास'। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अर्नब राय चौधरी, भौतिकी विभाग, आईआईएससी, बेंगलुरु ने की। विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉ नकुल पाराशर ने स्वागत भाषण दिया।

अपने दूरदर्शितापूर्ण संबोधन में प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने भारत में सौर भौतिकी की स्थिति और संभावना का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने देश भर में विभिन्न स्थानों पर मौजूद सौर सुविधाओं का विस्तृत विवरण देकर अपने व्याख्यान की शुरुआत की और विषय की तकनीकी बारीकियों को समझाया। उन्होंने बहु–अनुप्रयोग सौर दूरबीन, यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जैसे परिष्कृत उपकरणों के बारे में बात की, जो सूर्य, सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स आदि में अलग–अलग टाइमस्केल की परिवर्तनशीलता का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। प्रो बैनर्जी ने प्रस्तावित राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन के बारे में भी विस्तार से बताया जो कि 2एम क्लास ऑप्टिकल और देश में नियर इंफ्रा–रेड ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटी होगा। इसे 0.1–0.3 आर्क–सेकंड के स्थानिक विभेदन पर सौर चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति और गतिशीलता से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक मुद्दों की एक सारणी को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतरिक्ष–आधारित मिशन और जमीन–आधारित एमएएसटी टेलीस्कोप (उदयपुर) से बड़ी संख्या में सौर वायुमंडलीय पर्यवेक्षणों की सम्भाल और पुष्टि करने के लिए उपकरण में व्यापक प्रबन्ध है।

प्रो बैनर्जी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए शीघ्र ही शुरू होने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष–आधारित मिशन, आदित्य एल1, के बारे में भी बताया। यह इसरो के नेतृत्व वाला एक बहु–संस्थागत मिशन है और 2022 के मध्य में किसी भी समय इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। उपग्रह के सात पेलोड (उपकरण) सौर कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर पवनों और फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) का अध्ययन करेंगे, साथ ही यह सूर्य की छवियों को भी कैप्चर करेंगे। यह परियोजना सूर्य की गतिकीय प्रक्रियाओं पर व्यापक समझ को सक्षम करेगी और सौर भौतिकी में कुछ बड़ी समस्याओं का समाधान करेगी।

अंत में, प्रो बैनर्जी ने भारत में अगली पीढ़ी के सौर वैज्ञानिकों और भौतिकविदों को प्रशिक्षित करने में अपनी संस्था एआरआईईएस की भूमिका के बारे में बात की। आदित्य–एल1 सहायता कोष्ठिका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में स्थापित किया गया है, जो मुख्य रूप से अपेक्षित प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करेगा। इस संबंध में इस साल की शुरुआत में संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सपोर्ट सेल भारत में कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सूर्य से संबंधित संसाधित वैज्ञानिक डेटा के एक नमूने तक मुफ्त पहुंच प्राप्त करने के लिए वन–स्टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। सभी डेटा को इसरो के भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा केंद्र में होस्ट किया जाएगा, और एआरआईईएस सेल एक जनशक्ति प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ■

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के नए मोर्चे

दक्षिणीय सहयोग को प्रोत्साहन

आरआईएस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर समारोह।

आरआईएस ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, ताकि विकासशील देशों और उसके बाहर अपने विशेष विंग, ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर (जीडीसी) के माध्यम से विचारों, नवाचारों और समाधानों को सांझा कर उन्हें आगे बढ़ा सके। जीडीसीआरआईएस और बीएमजीएफ अन्य प्रमुख विकास मुद्दों के साथ–साथ पोषण, स्वास्थ्य प्रणाली, महामारी की तैयारी, कृषि, डिजिटल वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में दक्षिणीय सहयोग के लिए साझेदारी को मजबूत करने और नई साझेदारियाँ बनाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे।

यह साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति के लिए एक जीवंत, रचनात्मक और निरंतर जुड़ाव बनाने की दिशा में वैश्विक दक्षिण के बीच विकास नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस जुड़ाव में विकास समाधानों में नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और उनके दस्तावेजीकरण के लिए समस्तरीय और ऊर्ध्व एकीकृत साझेदारी और राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र, विचार मंडलों, नागरिक समाज और शिक्षाविदों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच बनाना शामिल होगा। इसका उद्देश्य ज्ञान आदान–प्रदान कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन सहायता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विचारों की साझेदारी को सुगम बनाना है। यह जुड़ाव दक्षिणीय सहयोग के व्यापक लक्ष्यों को मजबूत करने की दिशा में स्थानीय और विश्व स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को क्यूरेट करने में व्यापक समग्र समर्थन प्रदान करके भारत और वैश्विक दक्षिण में विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच को सक्षम करेगा।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि वैश्विक विकास केंद्र का हमारा आरंभिक विचार माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए कई प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, जिन्होंने हमारी

...शेष पृष्ठ 16 पर

डॉ राजकुमार रंजन सिंह, माननीय विदेश राज्य मंत्री

"इस अवसर पर बोलते हुए माननीय मंत्री ने कहा, "भारत को संकट के समय में क्षेत्र में सर्वप्रथम क्रियाशील होने वाला देश, एक जलवायु की दिशा में पहलकदमी करने में अग्रणी, विश्व के औषधालय, प्रतिभा के भंडार और एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में देखा जाता है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आरआईएस ने दक्षिणीय सहयोग के ढांचे के भीतर माननीय प्रधान मंत्री के विचारों को अन्य विकासशील देशों तक ले जाने के लिए अपने परिसर में एक विशेष केंद्र, ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर, (जीडीसी) की स्थापना की है। आरआईएस और बीएमजीएफ के बीच यह साझेदारी वैश्विक वस्तुओं को बढ़ावा देने की भारत की नीति के हिस्से के रूप में इच्छुक भागीदार देशों और संस्थानों के बीच ज्ञान के संस्थागत हस्तांतरण, ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए नीति अनुसंधान और आउटरीच को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और कौशल विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं एक बेहतर दुनिया के लिए इस रचनात्मक पहल के लिए आरआईएस में जीडीसी टीम और बीएमजीएफ के हमारे दोस्तों को बधाई देना चाहता हूं।"

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के नए मोर्चे

वैश्विक दक्षिण के लिए 'डिजिटल पब्लिक गुड्स'

जीडीसी की परियोजना को 'वैश्विक दक्षिण के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स बनाना' को दक्षिणीय सहयोग के तहत वैश्विक दक्षिण के समाधान के हिस्से के रूप में चुना गया है। इस परियोजना ने (कोविन) की अग्रणी उपलब्धियों को एशिया और अफ्रीका में उपयुक्त रूप से अपनाए जाने के लिए सर्वोत्तम प्रथा के रूप में व्यवस्थित किया।

इस वर्ष, जीडीसी ने वैश्विक स्तर पर कोविड–19 महामारी के अंतहीन प्रभाव के मद्देनजर पेरिस में 11–13 नवंबर के बीच पेरिस शांति मंच में भाग लिया। सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों, विशेष रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति आदरणीय इमैनुएल मैक्रों, नाइजीरिया के राष्ट्रपति आदरणीय मुहम्मदु बुहारी, बांग्लादेश की प्रधान मंत्री आदरणीय शेख हसीना, संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति आदरणीय कमला हैरिस सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। अन्य उल्लेखनीय प्रतिभागियों में सरकारी और गैर–सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठनों, परोपकारी संगठनों और विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों के प्रमुख शामिल थे।

जीडीसी के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंच में भाग लिया: डॉ मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस; श्री रोहित देव झा, उप निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, को–विन डिजिटल टीकाकरण मंच के तकनीकी विशेषज्ञ; और सुश्री रितुपर्णा बनर्जी, जीडीसी प्रबंधक; और श्री ओमगेरे जॉन पैट्रिक, जीडीसी रिसोर्स पर्सन, युगांडा प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

कोविड–19 द्वारा उत्पन्न भारी चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जीडीसी ने पेरिस पीस फोरम समिट 2021 में इस स्तर के एक प्रमुख वैश्विक मंच में शामिल होकर आउटरीच के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और बहु–हितधारक सहयोग को बढ़ावा दिया। ■

एसआईडीएस और जलवायु परिवर्तन पर भविष्य की रणनीतियां और दक्षिणीय सहयोग की प्रथाएं पर चर्चा

1 नवंबर, 2021 को एसआईडीएस और जलवायु परिवर्तन पर भविष्य की रणनीतियां: दक्षिणीय सहयोग प्रथाओं पर एक आभासी पैनल चर्चा आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन भेद्यता और एसआईडीसी के अस्तित्व को होने वाले खतरों से निपटने में दक्षिणीय सहयोग प्रथाओं और अनुभवों के संभावित उपयोग का विश्लेषण करना था। दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय, फिजी द्वीप समूह के डॉ एबरहार्ड एच वेबर और राजदूत विनोद कुमार ने चर्चा में भाग लिया और इस विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे जलवायु परिवर्तन एसआईडीएस के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रहा है और इन देशों के पास प्रभावी ढंग से चुनौतियों का सामना करने और उनसे निपटने के लिए संसाधन नहीं हैं। यह माना गया कि एसआईडीएस

में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन की सुविधा के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। परिचर्चा में व्यक्त विचारों को शोध पत्रों में विकसित किया जाएगा, जिसे जलवायु परिवर्तन और एसआईडीएस पर विकास सहयोग समीक्षा प्रकाशन के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाएगा। परिचर्चा का संचालन आरआईएस के विजिटिंग फेलो प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती ने किया। ■

महामारी और दक्षिणीय सहयोग के नए आयाम

भारतीय विकास सहयोग मंच, आरआईएस ने 18 अक्टूबर 2021 को 'महामारी और दक्षिणीय सहयोग के नए आयाम' विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। द ओस्लो एसडीजी इनिशिएटिव के निदेशक, प्रोफेसर डैन बानिक ने मुख्य व्याख्यान दिया। आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने प्रारंभिक टिप्पणी प्रस्तुत की। डॉ रुचिता बेरी, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, समन्वयक, अफ्रीका, लातिन अमेरिका और कैरेबियन और यूएन, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, ने विशेष टिप्पणी की। परिचर्चा का संचालन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर, प्रोफेसर अनुराधा चेनॉय ने किया।

एजेंडा 2030 की स्थिति पर और कैसे कोविड–19 महामारी के कारण स्थिति और खराब हो गई, इस पर प्रकाश डालने के लिए चर्चा का आयोजन किया गया था। कोविड–19 महामारी ने कई आर्थिक और सामाजिक संकटों के संदर्भ में कई देशों के विकास की गति को उलट दिया है। प्रोफेसर बानिक ने विकास की राजनीति पर विचार सांझा किये और 2030 एजेंडा से परे समाधान के बारे में सोचने का आग्रह किया। एसडीजी को पूरा करने के लिए दक्षिणीय सहयोग और त्रिकोणीय सहयोग की भूमिका पर भी जोर दिया गया। ■

सीओपी 26

सीओपी 26 से पहले और उसके दौरान के मुद्दे और चुनौतियां पर भारतीय परिप्रेक्ष्य

जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव पर बढ़ती चिंताओं और आगामी सीओपी 26 के महत्व को स्वीकार करते हुए, विज्ञान भारती (विभा) और आरआईएस ने संयुक्त रूप से सीओपी 26 की तैयारियों और फिर सम्मेलन के दौरान मुद्दे और चुनौतियां – भारतीय परिप्रेक्ष्य विषय पर 24 अक्टूबर, 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, में सलाहकार (जलवायु परिवर्तन) डॉ जे आर भट्ट को सीओपी 26 से पहले और उसके दौरान मुद्दों और चुनौतियों से संबंधित भारतीय दृष्टिकोण पर अपनी अंतर्दृष्टि देने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; राजदूत भास्कर बालकृष्णन, साइंस राजनय फेलो, आरआईएस और भारत के पूर्व राजदूत; डॉ लक्ष्मण सिंह राठौर, पूर्व महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग और विश्व मौसम विज्ञान संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि; और, श्री जयंत सहस्रबुद्धे, राष्ट्रीय आयोजन सचिव, विज्ञान भारती को विषय पर अपने विशेष विचार साझा किये।

अपनी प्रस्तुति में डॉ भट्ट ने जलवायु परिवर्तन के चेतावनी संकेतों, जलवायु सम्मेलनों की समयरेखा, शासन ढांचे और जलवायु परिवर्तन से जुड़े आख्यानों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत को उचित हिस्सेदारी का अधिकार है। भारत वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से को पार नहीं करेगा, लेकिन दूसरों द्वारा अधिक खपत की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। विकसित देशों को शेष कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शून्य के समय की घोषणा करनी चाहिए। उन्हें ऐतिहासिक कार्बन ऋण की भरपाई के लिए नकारात्मक उत्सर्जन के माध्यम से विकासशील देशों को कार्बन स्पेस प्रदान करना चाहिए। वर्तमान तापमान वृद्धि में भारत का योगदान बहुत कम है। हालांकि, भविष्य में जलवायु जोखिम का एक उच्च स्तर है। इसलिए, कृषि (पशुधन और मत्स्य पालन सहित), ग्रामीण आजीविका, वन और जैव विविधता, अनौपचारिक और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए समय चाहिए। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है। डॉ भट्ट ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के शुभारंभ जैसी कुछ पहलों पर चर्चा की। भारत उन क्षेत्रों में उद्योग अवस्थांतरण पर नेतृत्व समूह का स्वीडन के साथ मिलकर सह–नेतृत्व करता है, जिनमें परिवर्तन लाना इतना सरल नहीं है।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने जलवायु कार्रवाई में वित्त के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा प्रदान किया गया लगभग 71 प्रतिशत जलवायु वित्त ऋण के रूप में है, जो ज्यादातर बाजार दरों पर दिया गया है। ओइसीडी देशों के साथ विशाल अंतर को देखते हुए, दक्षिणीय सहयोग की अधिक आवश्यकता है। राजदूत भास्कर बालकृष्णन ने पूरी दुनिया के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि विकसित देशों को विकासशील देशों से पहले लक्ष्य हासिल करना चाहिए, और नकारात्मक उत्सर्जन के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। विकासशील देशों के लिए, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य लचीला होना चाहिए। भारत को किसी भी बाध्यकारी प्रतिबद्धता का अन्य देशों के साथ मिलकर विरोध करना चाहिए, हालांकि लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बशर्ते कि प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन उपाय मुहैया हों।

लक्ष्मण सिंह राठौर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामूहिक समस्या है, और इसके लिए वैश्विक और सामूहिक प्रयासों और कार्यों की आवश्यकता है। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और विविध हितधारकों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होगा। अपने समापन भाषण में श्री जयंत सहस्रबुद्धे ने जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। अन्त में धन्यवाद ज्ञापन अविनाश रायरिकर ने दिया। ■

द्विपीक्षीय व्यापार

प्रथम भारत–कोरिया 2+2 द्विपक्षीय वार्ता

आरआईएस, भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और कोरियाई राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी (केएनडीए) और कोरिया गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान (केआईईपी) ने 27 अक्टूबर 2021 को उभरती क्षेत्रीय व्यवस्था में भारत–कोरिया संबंधों की पुनर्कल्पनाः 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी और न्यू सदर्न पॉलिसी' का तालमेल पर पहली भारत–कोरिया 2+2 द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन सत्र से हुई। राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, आईसीडब्लूए; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; डॉ. होंग ह्यूनिक, चांसलर, केएनडीए; डॉ. किम ह्युंगचोंग, अध्यक्ष, केआईईपी; राजदूत चांग जे–बोक, भारत में दक्षिण कोरियाई राजदूत; और कोरिया गणराज्य में भारतीय राजदूत, राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने संवाद को संबोधित किया।

राजदूत नलिन सूरी, विशिष्ट फेलो, दिल्ली पॉलिसी ग्रुप ने बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ में भारत–कोरिया संबंधः सामरिक दृष्टिकोण पर सत्र की अध्यक्षता की। वक्ताओं में डॉ चो वोंडुक, अनुसंधान प्रोफेसर (केएनडीए); और डॉ जगन्नाथ पांडा, रिसर्च फेलो, मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली (एमपी–आईडीएसए) शामिल थे। डॉ जोजिन वी जॉन, रिसर्च फेलो, आईसीडब्ल्यूए; और डॉ पाइक वूयल, एसोसिएट प्रोफेसर, योन्सी विश्वविद्यालय ने परिचर्चा में भाग लिया।

कोविड–19 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारत–कोरिया आर्थिक साझेदारी को पुनर्संदर्भित करने वाले सत्र की अध्यक्षता सेंटर फॉर एरिया स्टडीज, केआईईपी, के उपाध्यक्ष डॉ चो चोंगजे ने की। प्रोफेसर एस. के. मोहंती, आरआईएस; और डॉ. हान ह्योंगमिन, एसोसिएट रिसर्च फेलो, केआईईपी, प्रमुख वक्ता थे। चर्चा में भाग लेने वाले थेः डॉ ली सून–चुल, प्रोफेसर, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज और डॉ प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस।

कोरिया गणराज्य के पूर्व भारतीय राजदूत स्कंद तायल ने आगे की राहः भारत–कोरिया द्विपक्षीय संबंध पर सत्र की अध्यक्षता की। वक्ता थेः डॉ किम चानवान, प्रोफेसर, हांकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज और डॉ जितेंद्र उत्तम, सहायक प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

समापन सत्र में चर्चा में शामिल थेः डॉ किम ह्यूंगचोंग, अध्यक्ष, केआईईपी; डॉ. होंग ह्यूनिक, चांसलर, केएनडीए; प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; और राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए। ■

एमसी–12 के स्थगन से अधिक काम की गुंजाइश बढ़ी

...शेष पृष्ठ 2 से जारी

कि वैश्विक दक्षिण एमसी–12 के विभिन्न मुद्दों पर एक एकजुट इकाई के रूप में बना रहे, जिसमें संयुक्त वक्तव्य पहल भी शामिल है। यह सुनिश्चित भी हो सके कि राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने में विकासशील देश के सरकार द्विपक्षीय संवाद नीति के अवसर से वंचित ना कर रहे। उन्होंने कहा कि व्यापार घरेलू उत्पादन और घरेलू विकास के लिए उत्प्रेरक होना चाहिए न कि केवल अधिक आयात के लिए। भारत को डब्लूटीओ मंत्रिस्तरीय के स्थगन का उपयोग दक्षिण के साथ जुड़ने के लिए करना चाहिए। आरआईएस के प्रो एस. के. मोहंती और डॉ पंखुरी गौर ने डब्लूटीडीआर का विवरण प्रस्तुत किया। और डॉ सब्यसाची साहा, आरआईएस ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये। ■

द्विपक्षीय संवादों के साथ आगे बढ़ना

महामारी के बाद भारत–अफ्रीका संबंधों पर चर्चा

हाइब्रिड मोड में चल रही गोलमेज चर्चा।

ओस्लो विश्वविद्यालय, नॉर्वे के सहयोग से आरआईएस ने 9 दिसंबर, 2021 को महामारी के बाद की दुनिया में भारत–अफ्रीका संबंध पर हाइब्रिड मोड में चर्चा का आयोजन किया। उद्देश्य था भारत–अफ्रीका संबंधों के भविष्य का आकलन करना। स्वास्थ्य, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता निर्माण, पारंपरिक चिकित्सा, आदि के क्षेत्रों में समग्र विदेश नीति अभिविन्यास और क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित यह चर्चा दो सत्रों में हुई।

अपने स्वागत भाषण में प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने भारत–अफ्रीका संबंधों के प्रमुख मील के पत्थर और साथ ही, उनकी विकास साझेदारी में हाल के रुझानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत आज विकास और अवसंरचना परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए अधिक उत्सुक है। प्रगति की निगरानी की पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की है। उन्होंने अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में विकास सहयोग की सुविधा के लिए भारत की विकास एजेंसी स्थापित करने का भी सुझाव दिया। नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डैन बानिक ने कहा कि अफ्रीका के प्रति भारत की पिछली नीति से अब बड़ा परिवर्तन आया है। हाल के दिनों में अधिक ऊंचे दर्जे के दौरे हुए हैं। भारत और अफ्रीका के बीच रक्षा सहयोग भी विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश नीति का आदर्शवाद से अधिक व्यावहारिकता की ओर झुकाव बदलाव का एक प्रमुख पहलू है।

भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव (ईआर) श्री दम्मू रवि ने अपनी विशेष टिप्पणी में कहा कि भारत के लिए अफ्रीका के साथ सहयोग हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। अफ्रीका के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करते हुए श्री रवि ने कहा कि वर्तमान में नई दिल्ली स्वास्थ्य, नवीकरणीय और आईटी–वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ा रही है। भारत ने कोविड के टीकों के अलावा अफ्रीकी देशों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की है और भविष्य में भी सहायता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन में अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने की भी गुंजाइश है। अफ्रीका में व्यापार की स्थिति उतनी ठीक नहीं है। आज अफ्रीका केवल कच्चे माल का निर्यात ही नहीं, विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण करना चाहता है। इसलिए, भारत अफ्रीकी देशों के सहयोग से वहां विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करना चाहेगा। श्री रवि ने कहा कि भारत अफ्रीका में फ्रांस और ब्रिटेन के साथ त्रिकोणीय सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है।

चर्चा में स्वास्थ्य और फिनटेक के क्षेत्रों में भारत–अफ्रीका सहयोग पर व्यापक रूप से विचार साझा किए गए। सहभागियों ने यह भी उल्लेख किया कि कृषि क्षेत्र भी भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग के अवसर प्रदान करता है।

यह भी सुझाव दिया गया कि भारत को अफ्रीका में यूरोपीय देशों के साथ, उनके औपनिवेशिक शासन के कारण, सहयोग विकसित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। चर्चा में यह भी कहा गया कि अफ्रीका में बहुत विविधता है, इसलिए भारत को अपनी अफ्रीका नीति को गैर–महाद्वीपीय बनानी चाहिए। ■

द्विपक्षीय वार्ता के साथ आगे बढ़ना

को–विन पर भारत–केन्या द्विपक्षीय सत्र

जीडीसी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारत के डिजिटल टीकाकरण प्लेटफॉर्म कोविन पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिभागियों के सामने, केन्याई सरकार द्वारा इसकी संभावित प्रतिकृति की संभावना का पता लगाने के लिए, एक प्रस्तुति दी।

इससे पहले, जीडीसी ने 19 मई, 2021 को 'कोविड से मुकाबला: वैक्सीन प्लेटफॉर्म और रोलआउट में विकासशील देशों के अनुभवों' पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में युगांडा, रवांडा, केन्या और नाइजीरिया के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। उसके बाद भी, जीडीसी लगातार इन देशों के संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करता रहा था, को–विन प्लेटफॉर्म को संभावित रूप से अपनाने या को–विन की तर्ज पर उनके मौजूदा टीकाकरण प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के अवसरों का पता लगाने के लिए।

प्रस्तुति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत के पर्याप्त अनुभव, विशेषज्ञता और क्षमताओं के माध्यम से केन्या को संभावित उन्नयन और/या आवश्यकता–आधारित उपयुक्त समाधान प्रदान करने के लिए रास्ते खोलना था।

27 अक्टूबर, 2021 को आयोजित तकनीकी सत्र की केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और केन्या के संबंधित तकनीकी टीम के सदस्यों ने खूब सराहना की। केन्या के तकनीकी अधिकारियों में से एक ने अपने देश के डिजिटल टीकाकरण मंच को विकसित करने में कई प्रगति के बारे में बताया। ग्लोबल साउथ में विकास के अनुभवों को एक जगह संगृहित करने और बढ़ावा देने के जीडीसी के जनादेश के अनुरूप, स्वास्थ्य मंत्रालय, केन्या के प्रधान सचिव से उनके टीकाकरण मंच का विवरण साझा करने के लिए संपर्क किया गया था। ■

विकास सहयोग

2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए विकास सहयोग की पालग्रेव पुस्तिका

'2030 एजेंडा हासिल करने के लिए विकास सहयोग की पालग्रेव पुस्तिका' के विमोचन के अवसर पर, 26 अक्टूबर, 2021 को नेस्ट, आरआईएस द्वारा एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें पुस्तिका के संपादक प्रोफेसर ली शियाओयुन, सीएयू; डॉ स्टीफ़न क्लिंगबील, डीआईई; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, आरआईएस; जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास के संघीय मंत्रालय के डॉ जर्गन कार्ल ज़ट्लर और रेडबौड विश्वविद्यालय के डॉ हेली स्वेडलंड शामिल थे। परिचर्चा का संचालन श्रीमान आर्टेम इज़मेस्टीव, यूएनओएसएससी, इस्तांबुल द्वारा किया गया था, जिसमें प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस द्वारा समापन टिप्पणी की गई थी।

पुस्तिका के संपादकों ने विकासशील देशों में अभ्यासियों के लिए पुस्तक के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। एजेंडा 2030 को सामूहिक रूप से हासिल करने के लिए विकास सहयोग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। चर्चा करने वालों ने आपसी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा के महत्व और विकासशील देशों को एक–दूसरे से सीखने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। ■

'2030 एजेंडा हासिल करने के लिए विकास सहयोग की पालग्रेव पुस्तिका' के विमोचन पर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस।

भारत–यूरोपीय संघ संपर्कः विकास और लोकतंत्र के लिए साझेदारी

भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत, यूगो एस्टुटो के अनुसार, भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) कनेक्टिविटी पार्टनरशिप यूरोपीय संघ की ग्लोबल गेटवे पहल का एक महत्वपूर्ण घटक होगा जिसका उद्देश्य दुनिया भर में वस्तुओं, सेवाओं, संस्थानों, बैंकों, व्यवसायों और लोगों को जोड़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना में निवेश के माध्यम से 'निर्भरता नहीं, संपर्क' बनाना है।

28 अक्टूबर 2021 को, आरआईएस द्वारा 'भारत–यूरोपीय संघ संपर्कः विकास, मांग और लोकतंत्र के लिए साझेदारी' शीर्षक से एक रिपोर्ट का अनावरण करते हुए, राजदूत एस्टुटो ने यह भी कहा कि यूरोपीय निवेश बैंक और निजी क्षेत्र की ताकत का लाभ भारत–यूरोपीय संघ सम्पर्क–सम्बन्ध साझेदारी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा।

आरआईएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए, श्री संदीप चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव (यूरोप पश्चिम), विदेश मंत्रालय, ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने सुनिश्चित किया है कि उनकी द्विपक्षीय सम्पर्क–सम्बन्ध साझेदारी 'उच्च मानक' की होगी, और लोगों से लोगों के संपर्क के साथ–साथ यह गतिशीलता पर भी केंद्रित है। उन्होंने कहा कि 'सुरक्षित और भरोसेमंद' आपूर्ति श्रृंखला बनाने के महत्व को देखते हुए द्विपक्षीय साझेदारी ने अन्य देशों और क्षेत्रों में समान विचारों को प्रेरित किया है। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस संदर्भ में व्यवहार्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही एक भारत–यूरोपीय संघ 'कनेक्टिविटी फोरम' शुरू करने की योजना है।

राजदूत (डॉ) मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस, ने भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी के कार्यनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय संपर्क समझौते के सफल कार्यान्वयन के लिए भारत–यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौतों पर बातचीत में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि आरआईएस रिपोर्ट में भारत–यूरोपीय संघ के व्यापार और निवेश, सम्पर्क–सम्बन्ध में सहयोग के क्षेत्रों का गहन विश्लेषण है। साथ ही, इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) का लाभ उठाकर सतत विकास और हरित संक्रमण के लिए कनेक्टिविटी का उपयोग करने के तरीके भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में संस्थागत दृष्टिकोण से वित्तीय संपर्क, जहां वित्तीय संस्थानों, बैंकों और फिनटेक के प्रदाताओं के बीच संबंधों की विस्तार से जांच की गई है, के अतिरिक्त वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों पर रोशनी डाली गई है, जैसे कि हरित हाइड्रोजन, सौर और अन्य प्रकार की गैर–पारंपरिक ऊर्जा।

बाद की परिचर्चा के दौरान, नीदरलैंड में भारत की पूर्व राजदूत, सुश्री भास्वती मुखर्जी ने संधारणीयता सहित सम्पर्क–सम्बन्ध सिद्धांतों पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच अभिसरण की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि साझेदारी समझौता वित्तीय और पर्यावरणीय संधारणीयता सहित उभरती चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के अध्यक्ष, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने कहा कि भारत–यूरोपीय संघ सम्पर्क–सम्बन्ध साझेदारी में तीसरी दुनिया के देशों में भी सम्पर्क–सम्बन्ध बढ़ाने के संबंध में बड़ी संभावनाएं और भू–राजनीतिक मूल्य हैं, और यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विकल्प होगा।

सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र के फेलो डॉ कांस्टेंटिनो जेवियर ने कहा कि चूंकि द्विपक्षीय सम्पर्क–सम्बन्ध साझेदारी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और पारदर्शिता और सुशासन के अलावा अंतर–संचालन पर जोर देती है, इसलिए यह क्षेत्रीय मानकों को निर्धारित करने में मदद कर सकती है और यहां तक कि एक वैश्विक संपर्क साझेदारी के गठन में भी मदद कर सकती है। भारत और यूरोपीय संघ का यह सुनिश्चित करने का निर्णय कि वे सरकारी स्तर पर नेतृत्व करेंगे और सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन एक भारी भूमिका नहीं निभाएंगे, एक और महत्वपूर्ण पहलू था।

प्रोफेसर एस के मोहंती, आरआईएस ने उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी गहन व्यापार भारत–यूरोपीय संघ व्यापार के मूल में है, जबकि उनके द्विपक्षीय सेवा व्यापार में पूरकताएं हैं। विकास वित्त के रुझानों के बारे में बोलते हुए, आरआईएस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ प्रियदर्शी दाश ने कहा कि अब ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंड पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच अधिक वित्तीय संपर्क की आवश्यकता है ताकि दोनों पक्षों को फिनटेक सहित अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद मिल सके। ■

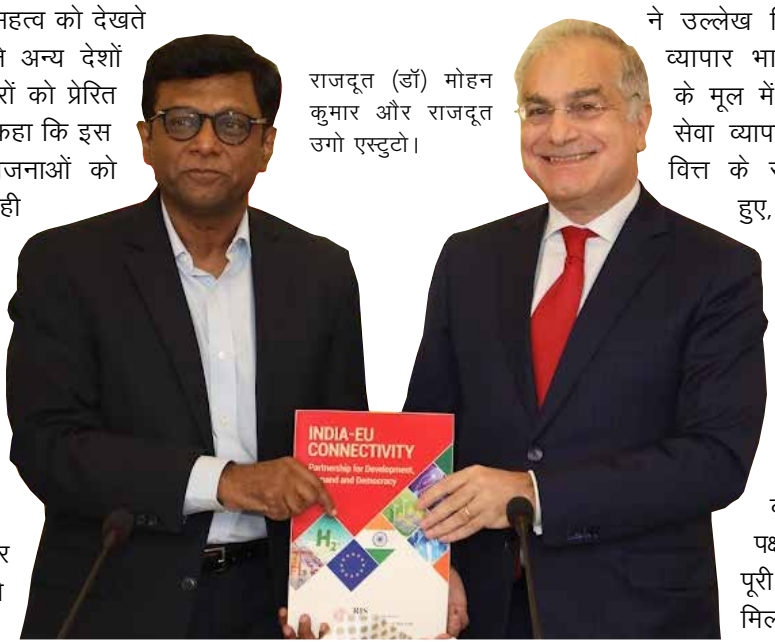

राजदूत (डॉ) मोहन कुमार और राजदूत उगो एस्टुटो।

बिम्सटेक क्षेत्र के साथ मिलकर आगे रहना

बिम्सटेक क्षेत्र में सतत कृषि विकास और मूल्य संवर्धन में सहयोग की खोज

28 अक्टूबर, 2021 को, आरआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के सहयोग से 'बिम्सटेक क्षेत्र में सतत कृषि विकास और मूल्य संवर्धन में सहयोग की खोज' पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें सदस्य राज्यों के विशिष्ट वक्ताओं, अध्यक्षों और पैनलिस्टों ने भाग लिया।

वेबिनार की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुई। उन्होंने सदस्य राज्यों के क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक कार्य, क्षेत्र में विकास की सीमाओं का विस्तार, निवेश के अवसरों की पहचान, और कई अन्य मुद्दों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। डॉ सुरेश बाबू, सीनियर रिसर्च फेलो और क्षमता सुदृढ़ीकरण के प्रमुख, एफपरी, वाशिंगटन ने इस क्षेत्र में गठबंधन की प्राथमिकता के महत्व की ओर इशारा करते हुए अपनी प्रारंभिक टिप्पणी दी। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि कैसे एक स्थायी खाद्य प्रणाली एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्रह एसडीजी में से नौ को प्रभावित करती है।.

उद्घाटन भाषण भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में अर्थशास्त्र क्षेत्र के प्रोफेसर सतीश वाई देवधर ने दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सम्पर्क–सम्बन्ध में प्रोत्साहन की आवश्यकता, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने, मौसम पूर्वानुमान, मूल्य श्रृंखला, ज्ञान साझा आदि के बारे में बात की और कृषि में एकतरफा उत्पादन की समस्या पर भी प्रकाश डाला।

उद्घाटन सत्र के बाद तीन सत्र थे। पहला तकनीकी सत्र 'बिम्सटेक में कृषि में व्यापार को बढ़ावा देना' विषय पर था। इसमें अध्यक्ष और विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए, खाद्य सुरक्षा और मूल्य श्रृंखला में व्यवधान का जोखिम है। श्रम उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता से उत्पादन करने, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा नियमों, क्षेत्रीय व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने आदि जैसे कई सुझाव भी दिए गए थे।

दूसरा तकनीकी सत्र 'बिम्सटेक में खाद्य प्रसंस्करण और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं की संभावनाओं' पर था, जिसमें बाधाओं को दूर करने और उन पर काबू पाने, मूल्य श्रृंखला में किसानों की उच्च भागीदारी, कृषि स्तर पर पैकेजिंग में सुधार, विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य उपक्षेत्रों में उच्च क्षेत्रीय प्रदर्शन, मूल्य श्रृंखला उन्नयन, डेटा का कुशल उपयोग और बेहतर डेटा संग्रह, आदि का सुझाव दिया गया था। 'कृषि में खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दे' पर हुए तीसरे सत्र में कृषि और पोषण के बीच गठजोड़ पर ध्यान देने, उपज में विविधता लाने, खाद्य हानि और अपशिष्ट को कम करने पर खर्च करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ध्यान देने

आदि पर फोकस करने की ओर इशारा किया गया।

डॉ सुरेश बाबू की अध्यक्षता में समापन सत्र का कार्यक्रम समाप्त हुआ। प्रमुख सिफारिशें डॉ प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस द्वारा प्रस्तुत की गईं। विदाई भाषण श्री हान थीन क्याव, प्रभारी निदेशक (कृषि सहयोग), बिम्सटेक सचिवालय, ढाका, बांग्लादेश द्वारा दिया गया। डॉ अमित कुमार, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस, नई दिल्ली ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। ■

बिम्सटेक: विकास और प्रगति का एक साधन

25–26 अक्टूबर 2021 को 'बिम्सटेकरू ए व्हीकल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट' (बिम्सटेकः विकास और प्रगति का एक साधन) पर एक रोचक संगोष्ठी हुई। इसे सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (Institute of Social and Cultural Studies – ISCS), कोलकाता और RIS द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उद्घाटन सत्र में, आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में परिवहन कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी, पारंपरिक दवाओं के महत्व और कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय विकास बैंकों की क्षमता का दोहन करने के बारे में बात की। आईएससीएस, भारत (ISCS, India) के निदेशक श्री अरिंदम मुखर्जी ने आतंकवाद, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, व्यापार और समुद्री सहयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

बिम्सटेक के महासचिव महामहिम राजदूत तेनजिन लेचफेल ने एक विशेष भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बिम्सटेक क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान पर चर्चा की, और क्रॉस–कंट्री संगठित अपराध, समुद्री संपर्क, मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों और सुरक्षा को सहयोग के क्षेत्रों के रूप में की पहचान करने पर जोर दिया। उन्होंने भारत में बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र और बिम्सटेक चार्टर की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव, महामहिम राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने उद्घाटन भाषण दिया और माल की सीमा पार आवाजाही, ऊर्जा, बिजली (पावर ग्रिड कनेक्टिविटी), व्यापार, तटीय सुरक्षा, समुद्री संपर्क, आतंकवाद का मुकाबला और पर्यटन में क्षेत्रीय सहयोग पर कई बहुमूल्य सुझाव दिए।

दो–दिवसीय संगोष्ठी में चार तकनीकी सत्र हुए। पहला तकनीकी सत्र "कोविड–पश्चात आर्थिक सुधार और बिम्सटेक में विकास की

गति को बहाल करना" पर था, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। पैनलिस्टों ने चर्चा को सतत विकास, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली को विकसित करने, हरित पुनरूप्राप्ति में निवेश करने और महिला श्रम बल की भागीदारी में सुधार करने पर केंद्रित करते हुए सदस्य देशों के साझा हितों और बिम्सटेक के माध्यम से एक मंच के रूप में उन्हें सामने लाने के लिए सहयोग में तीसरे स्थान (नागरिक समाज और व्यवसाय) को शामिल करने का सुझाव दिया। सत्र में नीली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, ज्ञान साझाकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के महत्व पर भी चर्चा की गई।

दूसरा तकनीकी सत्र 'क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना, और कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा की भूमिका' पर था, जिसमें वक्ताओं ने क्षेत्रीय निवेश उदारीकरण, सदस्य राज्यों में एसईजेड को बढ़ावा देने और बीबीआईएम जैसी अधिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं का सुझाव दिया। सत्र में, वक्ताओं ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे सार्क शिखर सम्मेलन की समाप्ति बिम्सटेक को दक्षिण एशिया में एक सहयोग मंच के रूप में अधिक प्रमुखता से सामने आने का अवसर प्रदान करती है।

तीसरा तकनीकी सत्र 'सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में क्षेत्रीय सहयोग' पर था। इस सत्र में, वक्ताओं ने चर्चा की कि कैसे महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान और सामान्य परिस्थितियों में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को उजागर किया है। साथ ही, निगरानी और सूचना प्रसार, चिकित्सा में आईसीटी के उपयोग, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने, स्वास्थ्य पर लोगों की जेब पर पड़ने वाले खर्च को कम करने, ज्ञान साझा करने और क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सा के समन्वेषण के लिए सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया। सत्र के विशेष संबोधन में भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पार्थ ने साइबर सुरक्षा और संबंधित खतरों पर भी चर्चा की।

चौथा और अंतिम तकनीकी सत्र 'आपदा प्रबंधन, समुद्री सहयोग और तटीय सुरक्षा' पर था। वक्ताओं द्वारा चिह्नित बिंदुओं में पायरेसी, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, प्रदूषण नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, नीली अर्थव्यवस्था, डेटाबेस का विकास, नेटवर्किंग, सूचना साझाकरण और क्षमता निर्माण शामिल थे। समुद्री सहयोग पर विशेष रूप से बल दिया गया क्योंकि इस क्षेत्र की तटरेखा बहुत बड़ी है और बंगाल की खाड़ी सदस्य देशों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है।

संगोष्ठी का समापन राजदूत सुमित नकंदला की अध्यक्षता में एक समापन सत्र के साथ हुआ, जो भारत–लंका अध्ययन (Indo–Lankan Studies), पाथ फाइंडर फाउंडेशन, श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक (पूर्व महासचिव, बिम्सटेक) हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पीपी एंड आर डिवीजन (PP&R Division) में संयुक्त सचिव राजदूत डॉ अनुपम रे ने विशेष टिप्पणी की। भारत में जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सुरंजन दास ने एक विशिष्ट वक्ता के रूप में भाग लिया, और RIS, भारत में सहायक प्रोफेसर डॉ प्रियदर्शी दाश ने संगोष्ठी रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति दी। ISCS, भारत में कार्यक्रम समन्वयक श्री कृष्णु बक्सी (डत ज्ञतपीदकन ठोप) ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। ■

आसियान–भारत

आसियान–भारत सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधी संपर्क पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

वियतनाम इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन एंड साउथवेस्ट एशियन स्टडीज के सहयोग से आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने आसियान–भारत सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधी संपर्क पर 7–8 अक्टूबर, 2021 को हनोई और नई दिल्ली में संकर मोड में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

तीसरा संस्करण दो दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें पांच पूर्ण सत्र और सांस्कृतिक सहयोग पर एक विशेष सत्र शामिल था। पांच पूर्ण सत्र थेः (1) समकालीन सांस्कृतिक बातचीत और विविधता, (2) संस्कृति और डिजिटलीकरण, (3) संस्कृति और पर्यटन, (4) शिक्षा और युवा, और (5) साझा विरासत।

इस सम्मेलन में विषय विशेषज्ञों, विद्वानों, चिकित्सकों, राजनयिकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के साथ आसियान देशों और भारत के कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आरआईएस, नई दिल्ली के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी; प्रो डॉ डांग गुयेन एन्ह, उपाध्यक्ष, वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी (वीएएसएस), हनोई; राजदूत प्रणय वर्मा, वियतनाम में भारत के राजदूत, हनोई; राजदूत फाम सान चाऊ, भारत में वियतनाम के राजदूत; और श्री ट्रॅन डुक बिन्ह, उप महासचिव (डीएसजी) आसियान समुदाय और कॉर्पोरेट मामलों के लिए, आसियान सचिवालय, जकार्ता द्वारा विशेष टिप्पणी की गई। महामहिम श्री गुयेन क्वोक जुंग, उप विदेश मंत्री और आसियान सोम नेता, वियतनाम ने उद्घाटन भाषण दिया। विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय, डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने मुख्य भाषण दिया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के अध्यक्ष डॉ मोहन कुमार ने की। महामहिम सुश्री पेन मोनी मकरा, राज्य सचिव और सोमका अध्यक्ष, कंबोडिया ने समापन सत्र में एक विशेष भाषण दिया। राजदूत रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने समापन भाषण दिया। आसियान, जकार्ता में भारत के राजदूत जयंत एन खोबरागड़े और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय (एएससीसी), आसियान सचिवालय, जकार्ता के लिए आसियान के उप महासचिव श्री कुंग फोक ने भी सम्मेलन में विशेष टिप्पणी की। वीआईआईएसएएस और आरआईएस में आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) की ओर से क्रमशः डॉ फाम काओ कुओंग और प्रो प्रबीर डे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। ■

भारत–आसियान संबंधों में गहनता लानाः जुड़ाव की नई राहें तलाशना

एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने आरआईएस में आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) और आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल (एआईबीसी) के सहयोग से 18वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2021 से पहले 'भारत–आसियान संबंधों में गहनता लानाः जुड़ाव की नई राहें तलाशना' पर 18 अक्टूबर, 2021 को आभासी मोड में एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार कार्यक्रम का लक्ष्य भारत–आसियान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से जुड़े मौजूदा मुद्दे, क्षेत्रीय व्यापार और एकीकरण को और विस्तारित करने के लिए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने, और कोविड–19 के बाद की दुनिया में अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना था। उद्घाटन भाषण सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक, निर्यात–आयात बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था। जबकि

विशेष संबोधन दातो रमेश कोडम्मल, सह–अध्यक्ष, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल (एआईबीसी), कुआलालंपुर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, द्वारा दिया गया था। सुश्री रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। इस वेबिनार में इंडिया एक्ज़िम बैंक रिसर्च प्रकाशन 'मूल्य श्रृंखला का निर्माणः भारत और आसियान के लिए अवसर' का भी विमोचन किया गया। डॉ प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी, आरआईएस, नई दिल्ली ने पैनल चर्चा का संचालन किया, जिसमें हिस्सा लेने वालों में विशेषज्ञ थे – डॉ राजन रत्न, उप–प्रमुख और वरिष्ठ आर्थिक मामलों के अधिकारी, यूएनएस्केप, नई दिल्ली; प्रोफेसर रूथ बानोमॉन्ग, डीन, थम्मासैट बिजनेस स्कूल, थम्मासैट विश्वविद्यालय, बैंकॉक; सचिव कार्लिटो जी गैल्वेस, जूनियर, शांति प्रक्रिया पर राष्ट्रपति के सलाहकार कार्यालय, मुख्य कार्यान्वयनकर्ता और वैक्सीन ज़ार, कोविड–19 के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य बल, फिलीपींस सरकार; और श्री मोहम्मद इरशाद, आसियान के लिए कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एशिया पैसिफिक, सिंगापुर। निर्यात–आयात बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री डेविड सिनेट ने समापन टिप्पणी दी और धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

दक्षिणीय सहयोग को प्रोत्साहन

...शेष पृष्ठ 6 से जारी

आर्थिक विकास पहलों में समावेशन और स्थिरता लाने के प्रयास में बहुत योगदान दिया है। ये दो आयाम हमारे द्वारा शुरू किए गए लगभग सभी कार्यक्रमों की मुख्य ताकत रहे हैं, जैसे आधार सक्षम ई–भुगतान सेवाएं या यूपीआई या भीम या यहां तक कि राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, आदि। ये कार्यक्रम लीकेज को रोककर, भारत के सबसे वांछित समुदायों को लाभ लक्षित करते हुए लाभार्थियों की पहचान करके सत्तता, समावेशन और शासन में दक्षता लाने के विचार की दिशा में योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

इस अवसर पर, गार्गी घोष, अध्यक्ष, ग्लोबल पॉलिसी एंड एडवोकेसी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि वैश्विक मंच पर वैक्सीन निर्माण और डिजिटल स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल वित्तीय समावेशन और उससे आगे तक भारत का नेतृत्व के महान उदाहरण हैं, जो क्रॉस–लर्निंग और सहयोग के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। हम विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ इस जुड़ाव को लेकर उत्साहित हैं और आशा करते हैं कि यह मंच वैश्विक दक्षिण में विस्तारित साझेदारी के अवसर प्रदान करेगा और संधारणीय विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देगा।

सहयोग के महत्व के बारे में बात करते हुए, बीएमजीएफ के इंडिया कंट्री डायरेक्टर, श्री हरि मेनन ने कहा कि अनुसंधान में तेजी लाने, नए उपकरण विकसित करने और स्वास्थ्य और विकास में निरंतर प्रगति के लिए सहयोग और साझेदारी अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक भागीदारी के लिए भारत सरकार की गहरी प्रतिबद्धता के ध्यान में रखते हुए, वैश्विक दक्षिण में स्वास्थ्य और विकास में सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने वाली संयुक्त प्रतिबद्धता और साझा शिक्षा को सक्षम करने में सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों, शिक्षाविदों और स्वैच्छिक और निजी क्षेत्रों के बीच मजबूत सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बीएमजीएफ को विदेश मंत्रालय और आरआईएस के साथ काम करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। ■

आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2021: प्रमुख तथ्य

38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रम अक्टूबर 2021 के अंतिम सप्ताह में हुए। आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने एशियन कोनफलूयनस के सहयोग से 18 नवंबर 2021 को 'आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2021: प्रमुख तथ्य, 2021 पर एक वेबिनार का आयोजन किया। विभिन्न आसियान देशों और भारत के युवा छात्रों और शोध छात्रों ने वेबिनार में भाग लिया और हाल ही में आयोजित आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा की। वेबिनार में आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा की गई। एशियन कॉन्फ्लुएंस के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची दत्ता द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक, आसियान इंडिया सेंटर (एआईसी), आरआईएस, नई दिल्ली ने पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। पैनलिस्ट में सुश्री जोआन लिन वेइलिंग, लीड रिसर्चर, आईएसईएएस–यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट, सिंगापुर; डॉ वो जुआन विन्ह, उप महानिदेशक, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, वीएएसएस, वियतनाम; डॉ सृष्टि पुखरेम, सीनियर रिसर्च फेलो, इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली; श्री सुपावित केवखुनोक, शोधकर्ता, थाईलैंड राजनीतिक डेटाबेस अनुसंधान केंद्र, बैंकॉक; सुश्री महिमा दुग्गल, रिसर्च एसोसिएट, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज (सीएपीएस), नई दिल्ली और डॉ संपा कुंडू, सलाहकार, एआईसी, आरआईएस, नई दिल्ली शामिल थे। ■

ब्रिक्स को बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के प्रयासों को मजबूत करने की जरूरत

...शेष पृष्ठ 4 से जारी

ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं को प्रेरणा के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर देखने के बजाय उनके लिए क्या सही है, इसके बारे में स्वयं विचार करना होगा। अंतर–ब्रिक्स आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। डॉ सुब्रमण्यन ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग और सामूहिक ताकत जुटाना विकास लाभांश और व्यवस्थित आर्थिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड बाजारों को विकसित, एकीकृत और गहन करने के लिए, ब्रिक्स देश वित्तीय विनियमन पर सहयोग बढ़ाएं, विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी और साथ ही 'ब्रिक्स बॉन्ड फंड' के संदर्भ में।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने जोर देकर कहा कि टीकाकरण मंच– कोविन के साथ–साथ जनधन–आधार–मोबाइल, ट्रिनिटी या बैंक खाते, डिजिटल पहचान और मोबाइल फोन–आधारित डिजिटल लेनदेन के माध्यम से मानव–केंद्रित डिजिटल वैश्विक सार्वजनिक वस्तु संरचना बनाने के भारत के विचार का अब वैश्विक दक्षिण द्वारा उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह आर्थिक सुधार के साथ–साथ सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने पर काम करता है। उन्होंने जोर दिया कि ब्रिक्स देशों को हरित वित्त, हरित हाइड्रोजन और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहिए क्योंकि इनका केन्द्र आर्थिक सुधार और विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है।

इस अवसर पर अन्य वक्ताओं में शामिल थे – प्रोफेसर यारीगीना इरीना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग, एमजीआईएमओ विश्वविद्यालय, रूस; प्रोफेसर हैहोंग गाओ, प्रोफेसर और निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त अनुसंधान केंद्र, विश्व अर्थशास्त्र और राजनीति संस्थान, चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी और प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल, एडजंक्ट सीनियर फेलो, आरआईएस।

उपरोक्त के अलावा, आरआईएस ने निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए; अफ्रीका के साथ अभिनव वित्तपोषण भागीदारी; समुद्री सुरक्षा सहयोग; नवाचार प्रोत्साहन पर भारतीय परिप्रेक्ष्य; स्वास्थ्य प्रभाव कोष; जलवायु–तैयार समुदायों का निर्माण; सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; और एसआईडीएस और जलवायु परिवर्तन के लिए भविष्य की कार्यनीति। ■

आसियान–भारत एफटीए की समीक्षाः भारत–इंडोनेशिया आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने की संभावनाओं और चुनौतियों की पहचान करना

आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र और इंडोनेशिया के दूतावास ने संयुक्त रूप से आभासी प्रारूप में भारत–इंडोनेशिया आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने की संभावनाओं और चुनौतियों की पहचान करने के लिए आसियान–भारत एफटीए पर एक ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन 29 नवम्बर, 2021 को किया। श्री मस्नी एरिज़ा, मिशन के उप प्रमुख, दिल्ली में इंडोनेशियाई दूतावास; और श्री विश्वास विदु सपकाल, संयुक्त सचिव (दक्षिण और हिंद–प्रशांत), विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया। सत्र का संचालन डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक, आसियान–भारत केंद्र (एआईसी), आरआईएस, नई दिल्ली द्वारा किया गया था। प्रमुख वक्ता थेः श्रीमती दीना कुर्नियासारी, आसियान वार्ता की निदेशक, व्यापार मंत्रालय, इंडोनेशिया; सुश्री इंदु नायर, निदेशक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत; डॉ लीना एलेक्जेंड्रा, वरिष्ठ शोधकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (सीएसआईएस), जकार्ता; और श्री प्रणव कुमार, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली। प्रख्यात पैनल ने आसियान–भारत एफटीए समीक्षा के आलोक में भारत–इंडोनेशिया आर्थिक जुड़ाव की संभावनाओं पर चर्चा की। ■

आसियान–भारत कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन का दोहन

आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र ने 18वें आसियान–भारत और 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से पहले 21 अक्टूबर 2021 को 'आसियान–भारतः कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन का दोहन' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पैनल में विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति नियोजक और व्यवसायी शामिल थे। इस अवसर पर वेबिनार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के अवसरों, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, कोविड –19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और चुनौतियों एवं कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। 'त्रिपक्षीय राजमार्ग और कंबोडिया, लाओ पीडीआर और वियतनाम तक इसका विस्तारः पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास निहितार्थ' शीर्षक के साथ एआईसी–आरआईएस की रिपोर्ट जारी की

गई। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया और आरआईएस के अध्यक्ष डॉ मोहन कुमार ने उद्घाटन भाषण दिया। सुश्री एलिस चेंग, उप उच्चायुक्त, भारत में सिंगापुर गणराज्य के उच्चायोग, नई दिल्ली और राजदूत जयंत एन खोबरागड़े, आसियान, जकार्ता में भारतीय राजदूत द्वारा विशेष टिप्पणियां दी गईं। डॉ प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक, आरआईएस में एआईसी,

...शेष पृष्ठ 18 पर जारी

समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पांचवां ईएएस सम्मेलन

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ), नई दिल्ली, आरआईएस, में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी), और पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र, कोलकाता के साथ साझेदारी में संकर मोड में 23–24 नवंबर, 2021 को कोलकाता में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पांचवें ईएएस सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजकों की ओर से डॉ प्रबीर डे, कैप्टन सरबजीत सिंह परमार और मेजर जनरल अरुण रॉय ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान, महानिदेशक, राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन; और पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, अध्यक्ष, पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय अध्ययन अनुसंधान केंद्र, कोलकाता द्वारा विशेष टिप्पणी दी गई। सुश्री मेगन जोन्स, निदेशक, क्षेत्रीय समुद्री जुड़ाव और कार्यक्रम, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामले और व्यापार विभाग (डीएफएटी), कैनबरा ने विशेष भाषण दिया। मुख्य भाषण राजदूत रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिया गया।

दो दिवसीय सम्मेलन में पांच पूर्ण सत्र थेः (1) समुद्री सुरक्षा, (2) संसाधन साझा करना, (3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, महामारी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, (4) समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वें ईएएस सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र पर सूचना और संसाधनों की साझेदारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, आपदा जोखिम में कमी और महामारी प्रबंधन और आगे की राह पर एक परिचर्चा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। हिंद–प्रशांत महासागरीय पहल और इसके सात स्तंभों के महत्व पर चर्चा हुई, जिनमें इस क्षेत्र में भारत की व्यावहारिक कूटनीति को मजबूत करने की क्षमता है। आईपीओआई प्रतिभागी देशों के साझा हितों के बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित है। हिंद–प्रशांत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के अभिसरण को सुविधाजनक बनाने की तत्काल आवश्यकता है और आईपीओआई ऐसे परिदृश्य के लिए उपयुक्त है। ■

आसियान–भारत कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन का दोहन

...शेष पृष्ठ 18 जारी से जारी

ने परिचर्चा की अध्यक्षता की और 'त्रिपक्षीय राजमार्ग और कंबोडिया, लाओ पीडीआर और वियतनाम तक इसका विस्तारः पूर्वोत्तर भारत के लिए निहितार्थ' पर एक प्रस्तुति दी। सत्र के वक्ता थे – डॉ अंबुमोझी वेंकटचलम, अनुसंधान रणनीति और नवाचार के निदेशक, आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता; श्री सो उमेज़ाकी, निदेशक, आर्थिक एकीकरण अध्ययन समूह, विकास अध्ययन केंद्र, विकासशील अर्थव्यवस्था संस्थान (आईडीई–जेट्रो), चिबा, जापान; श्री भरत जोशी, निदेशक, एसोसिएटेड कंटेनर टर्मिनल्स लिमिटेड (एसीटीएल), नई दिल्ली; प्रोफेसर सीएच प्रियरंजन सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल; डॉ टिन हटू नाइंग, निदेशक, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज केंद्र (सीईईएस म्यांमार), म्यांमार; और डॉ फाम काओ कुओंग, कार्यवाहक उप महानिदेशक, वियतनाम भारतीय और दक्षिण पश्चिम एशियाई अध्ययन संस्थान। डॉ संपा कुंडू, सलाहकार, एआईसी, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

भारत में जीवीसी विकसित करना: भारत में ताइवान के निवेश को बढ़ाना

कोविड–19 महामारी ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की भेद्यता को उजागर किया, जो कि उच्च श्रम शक्ति की आवश्यकताओं के कारण उद्योगों को विवश करती है, जैसे कि विनिर्माण उद्योग उत्पादन बंद करने के लिए विवश थे। तालाबन्दी के चरणों के दौरान महामारी का प्रभाव और भी बढ़ गया था, जिसने औद्योगिक क्षेत्रों में मंदी को उत्प्रेरित किया। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और भी अधिक हानिकारक थी, जिनकी जीडीपी में, सरकार के अनुमान के अनुसार, 2020–21 में 7.3 प्रतिशत की कमी आई, जबकि दुनिया में –3.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए, वैक्सीन उपलब्धी और आर्थिक सुधार में वृद्धि के साथ–साथ जीवीसी के क्षेत्रों और संभावित भौतिक क्षेत्रों की पहचान करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उत्पादों पर भारत और ताइवान के लंबे आपूर्ति श्रृंखला सहयोग के आधार पर, 'भारत में जीवीसी विकसित करना: भारत में ताइवान के निवेश को बढ़ाना' विषय पर वेबिनार, जो कि 9 दिसंबर, 2021 को हुआ, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के मुद्दे पर केंद्रित था। विषयों में शामिल थे (1) इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में ताइवान के अनुभव; (2) इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी क्षेत्रों और अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) उद्योगों के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण और वर्तमान विकास; और (3) प्रौद्योगिकी उद्योग आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत–ताइवान सहयोग – सरकारों की भूमिकाएं और व्यावसायिक दृष्टिकोण। यह अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, कोविड–19 महामारी और वैश्विक आर्थिक उथल–पुथल से निपटने में प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग पर भारत और ताइवान के बीच समझ को गहरा करेगा। भारत और ताइवान के बीच संवाद में वृद्धि और भविष्य में दोनों देशों के घनिष्ठ व्यापार भागीदार बनने से दोनों पक्षों को लाभ होगा।

प्रतिभागियों में शामिल थे: प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; डॉ चुआंग–चांग चांग, अध्यक्ष, चुंग–हुआ आर्थिक अनुसंधान संस्थान (सीआईईआर), ताइवान; डॉ क्रिस्टी सुन त्जु, सू, निदेशक, सीआईईआर; डॉ शिन–हॉर्नग, चेन, रिसर्च फेलो, निदेशक, द सेकेंड रिसर्च डिवीजन, चुंग हुआ इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक रिसर्च, ताइवान; अश्विनी के अग्रवाल, निदेशक, अप्लाइड मटीरियल्स, भारत; राजदूत अनिल वाधवा, पूर्व भारतीय राजदूत और विशिष्ट फेलो, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ); डॉ संजीव के वार्ष्णेय, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली; डॉ चुएन–हुई, हंग, उप महा निदेशक, मार्केट इंटेलिजेंस एंड कंसल्टिंग इंस्टीट्यूट (एमआईसी), इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, ताइवान। (रिकॉर्ड की गई प्रस्तुति); श्री सुनील आचार्य, उपाध्यक्ष, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन; और श्री ग्रांट कुओ, सीईओ और संस्थापक, डिजिटल डॉक्टर प्राइवेट लिमिटेड, भारत। ■

आईईए के 104वें वार्षिक सम्मेलन में सतत विकासशील अर्थव्यवस्था पर फोकस के साथ नवाचार और डेटा

आरआईएस ने 26 दिसंबर, 2021 को भोपाल में सतत विकासशील अर्थव्यवस्था पर फोकस के साथ नवाचार और डेटा पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इसमें शामिल प्रख्यात प्रतिभागी थे: प्रोफेसर शमिका रवि, पूर्व सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, तथा अनुसंधान निदेशक, द ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट, दिल्ली; प्रोफेसर ऋषिकेश टी कृष्णन, निदेशक, आईआईएम, बैंगलोर; नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर अन्ना रॉय; प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, आरआईएस; डॉ अंकुश अग्रवाल, आईआईटी, नई दिल्ली; और प्रोफेसर डी के नौरियाल, पूर्व कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल। ■

कंचनजंगा संवाद

28 दिसंबर, 2021 को आयोजित यह विचार–मंथन सत्र भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल के शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और सामुदायिक विकास व्यवसायियों को सामुदायिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्तीय और अवसंरचना विकास आदि के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के मुद्दों के साथ–साथ चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ ले आया। विषयगत रूप से, स्थानीय और जमीनी स्तर के विकास और प्रथाओं के मुद्दों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पर्यावरण–पर्यटन, जैविक भोजन, पुष्पकृषि, सांस्कृतिक बातचीत आदि के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पड़ोसी देशों में विकास सहयोग और सामुदायिक प्रथाओं के लिए उप–क्षेत्रीय तंत्र की सुविधा के लिए विचार–विमर्श और संवाद के लिए एक अकादमिक मंच के रूप में संकल्पित, पहली कंचनजंगा वार्ता फरवरी 2022 में सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में होगी। ■

39वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान

22 दिसंबर, 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 39वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी बॉम्बे, ऊर्जा स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक और मध्य प्रदेश राज्य के लिए सौर ऊर्जा के ब्रांड एंबेसडर द्वारा दिया गया था। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय था: 'सौर के माध्यम से भारत में ऊर्जा स्वराज्य को साकार करना: ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शमन सुनिश्चित करना'। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ भास्कर बालकृष्णन (ग्रीस में भारत के पूर्व राजदूत), विज्ञान राजनेय, आरआईएस ने की। डॉ कृष्णा रवि श्रीनिवास ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद डॉ विभा धवन, डीजी, टेरी और श्री सुनीत टंडन, निदेशक, इंडिया हैबिटेट सेंटर ने संक्षिप्त टिप्पणी की।

अपने बहुत ही व्यावहारिक और विचारोत्तेजक संबोधन में, प्रोफेसर चेतन एस सोलंकी ने बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की घटना के संदर्भ में मौजूदा खतरनाक स्थिति का अवलोकन प्रस्तुत किया, जो मानव प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला और इस पृथ्वी पर उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस खतरनाक स्थिति में निर्णायक कारक जीवाश्म ईंधन यानी तेल, गैस और कोयले से प्राप्त ऊर्जा का विशाल उत्पादन और उपयोग है। आज, 80–85 प्रतिशत ऊर्जा खपत जीवाश्म ईंधन से होती है, जो कार्बन आधारित हैं; और जब उन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, तो वे वातावरण से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन–डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। सीओटू लगभग 300 वर्षों तक वातावरण में रहता है और ग्रीनहाउस गैस होने के कारण, यह पृथ्वी को विश्वव्यापी वार्मिंग की ओर ले जा रहा है, जो कि अगर अभी नहीं रोका गया तो यह विनाशकारी होगा। पिछले तीस वर्षों में गैर–जिम्मेदार मानवीय गतिविधियों ने वातावरण में सीओटू की सांद्रता की अत्यधिक बढ़ा दी है, जो अब लगभग 415 पीपीएम के खतरनाक स्तर पर है। प्रो सोलंकी ने विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच द्विभाजन की ओर इशारा किया और तर्क दिया कि विकास के लिए ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि आवश्यक है; जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए ऊर्जा आपूर्ति में कमी लाने की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रमुख चुनौती यह है कि जलवायु परिवर्तन को प्रभावित किए बिना विकास को कैसे संतुलित किया जाए। उन्होंने इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए कठोर और तत्काल उपाय करने की चेतावनी दी। इस तरह के समाधान की दिशा में, प्रो सोलंकी ने तत्काल (जहां भी संभव हो) सौ प्रतिशत सौर ऊर्जा पर निर्भर करने और आत्म निर्भर बनने और ऊर्जा स्वराज्य को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने ऊर्जा स्वराज्य को साकार करने की कुंजी के रूप में 'सीमित खपत' और 'स्थानीयकृत उत्पादन' के दोहरे सिद्धांतों को सामने रखा। उन्होंने आगे ऊर्जा स्वराज्य से आजीविका सृजन, ऊर्जा स्वतंत्रता, सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा अनुशासन, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता जैसे लाभों की गणना की।

अंत में, प्रो सोलंकी ने ऊर्जा स्वराज्य प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सभी के लिए तीन–चरणीय दृष्टिकोण के पक्ष का समर्थन किया। पहला कदम है, जितना हो सके ऊर्जा के उपयोग से बचना है (भले ही वह सौर ऊर्जा हो) – कम से कम एक तिहाई कम करने की कोशिश करके। दूसरा कदम अनुशासन का अभ्यास करके और कुशल उपकरणों का उपयोग करके जितना संभव हो सके ऊर्जा के उपयोग को कम करना है, और कम से कम एक तिहाई कम करने का प्रयास करना है; और तीसरा चरण जितना संभव हो उतना कम उत्पन्न करना है (यदि संभव हो तो, केवल एक तिहाई, वह भी स्थानीय रूप से!)। उन्होंने तर्क दिया कि जलवायु परिवर्तन को कम करने और ऊर्जा स्वराज्य प्राप्त करने के लिए बचें, न्यूनतम करें और उत्पन्न करें का यह सिद्धांत या नियम महत्वपूर्ण है। अंत में, उन्होंने ऊर्जा स्वराज्य को जन आंदोलन का स्वरूप देने की अपील की, क्योंकि इतने बड़े अनुपात की चुनौती को दूर करने के लिए अकेले सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। ■

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की; 25–26 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक संघ के 104वें वार्षिक सम्मेलन में 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेशः उभरती गतिशीलता (क्लदंउपबे)' और 'मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था' पर सत्र।
- 23 दिसंबर 2021 को इंदौर में मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो के दौरान आयोजित विज्ञान नीति और प्रशासन सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया।
- क्या वैश्विक आर्थिक जुड़ाव के लिए भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है, इस पर वेबिनार में 'व्यापार वार्ता के मुद्दों' पर एक प्रस्तुति दी? जी20 शिखर सम्मेलन, सीओपी26 और 17 दिसंबर 2021 को आईसीआरआइईआर और एडीबीआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित व्यापार चर्चा से कुछ विचार।
- 15 दिसंबर 2021 को सीआईआई पार्टनरशिप समिट के 27वें संस्करण में 'अनुसंधान समुदाय और नीति निर्माताओं की शक्ति का लाभ उठानाः थिंक 20 (टी20) की भूमिका' पर सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 14 दिसंबर 2021 को कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस द्वारा आयोजित वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट) में 'बियॉन्ड बॉर्डर्सः साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन द क्वाड' (सीमाओं से परेः क्वाड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग) पर सत्र का संचालन किया।
- 13 दिसंबर, 2021 को ताइवान–एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन (टीएईएफ) और ताओयुआन सिटी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'ताओयुआन में 2021 रेजिलिएंट सिटीज़ फोरम में सुशासन के माध्यम से सहभागी लोकतांत्रिक शहरों को बढ़ावा देनाः सतत अर्थव्यवस्था, सुशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' की प्रस्तुति दी।
- विज्ञान में रचनात्मकता का जश्न पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) के 7वें संस्करण के दौरान 11 दिसंबर, 2021 को आयोजित 'शमन और अनुकूलन उपायः कार्य योजना' पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- विकल्प की आवश्यकता पर द इंडियन फ्यूचर्स द्वारा 10 दिसंबर, 2021 को आयोजित इंद्रप्रस्थ भव्य रणनीति सम्मेलन (इंद्रप्रस्थ ग्रैंड स्ट्रैटेजी सम्मेलन) में 'उभरते वैश्विक आर्थिक मोर्चे' पर प्रस्तुति दी।
- जिग्नासा द्वारा 10 दिसंबर 2021 को आयोजित जिग्नासा आरोग्य मेला और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य में आयुष प्रणाली' पर चर्चा में पैनलिस्ट।
- 5 दिसंबर, 2021 को कलकत्ता विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व छात्र संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर 'क्या भारत की विदेश नीति अपने आर्थिक हितों को पूरा कर रही है' पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- 3 दिसंबर, 2021 को जापान इकोनॉमिक फाउंडेशन (जेईएफ) और चाइना इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट (सीआईआरडी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एशिया प्रशांत मंच 2021 में एशिया प्रशांत की विकास रणनीति पर एक प्रस्तुति दी।
- 1 दिसंबर 2021 को सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी), ढाका द्वारा आयोजित बांग्लादेश–भारत साझेदारी के 50 वर्षरू अगले 50 वर्षों की यात्रा की ओर पर संवाद के दौरान भारत बांग्लादेश व्यापार पर एक प्रस्तुति दी।
- सतत विकास उद्देश्यों के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों को बनाए रखने और सुधारने में जी20 की भूमिका पर 1 दिसंबर, 2021 को व्यापार और निवेश अनुसंधान नेटवर्क (टीआईआरएन) और आईआईएसडी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पैनल चर्चा में 'विकासशील देशों के दृष्टिकोण से सतत विकास लक्ष्यों को किस प्रकार विश्व व्यापार संगठन के नियमों में शामिल किया जा सकता है' पर एक प्रस्तुति दी।
- 30 नवंबर, 2021 को यूएन ईएससीएपी *के एपीसीटीटी* और डीएसआईआर द्वारा आयोजित संधारणीय विकास के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में '4IR प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने वाले वित्तीय साधनों' पर प्रस्तुति दी।
- 29 नवंबर, 2021 को प्रिया द्वारा 'विकास सहयोग के बदलते स्वरूपरू नागरिक समाज के लिए क्या भूमिकाएं?' पर आयोजित वर्चुअल संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया गया।
- 29 नवंबर 2021 को यूएनडीपी,

ओईसीडी और जी20 इटालिया द्वारा आयोजित सतत विकास और समावेशी वैश्वीकरण पर छठी यूएनडीपी–ओईसीडी–जी20 कार्यशाला में उत्तर–दक्षिण, दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग सहित सार्वजनिक वस्तुओं के प्रदान करने के लिए बहुपक्षवाद का नवीनीकरण पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।

- 28 नवंबर, 2021 को आईसीसीआर द्वारा आयोजित अगली पीढ़ी लोकतंत्र नेटवर्क कार्यक्रम में 'कोविड के बाद भारत की आर्थिक स्थिति' पर एक सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 27 नवंबर, 2021 को एसोसिएशन ऑफ एशिया स्कॉलर्स द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर समापन भाषण दिया।
- 24 नवंबर, 2021 को आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस में 'एक लचीली जैव चिकित्सा आपदा प्रतिक्रिया का निर्माणः कोविड–19 महामारी से सीख' पर आईसीएमआर तकनीकी सत्र के दौरान जैव सुरक्षा पर वैश्विक साझेदारी पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।
- 24 नवंबर, 2021 को ईएक्सआईएम बैंक और सीआईआई द्वारा आयोजित अफ्रीका के साथ अभिनव वित्तपोषण साझेदारी पर दूसरे सीआईआई शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के वित्तपोषण परिदृश्य को नेविगेट करने के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
- 24 नवंबर, 2021 को Centro कम Investigaciones कम Politica Internacional द्वारा सामरिक अध्ययन पर आयोजित छठे सम्मेलन में सामरिक विवादों के क्षेत्रों के रूप में स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर एक प्रस्तुति दी।
- 23 नवंबर, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान और टीआईआरएन द्वारा आयोजित विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय पहल पर एक संवादात्मक चर्चा में अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।
- 22 नवंबर, 2021 को ओईसीडी द्वारा आयोजित डीएसी बाहरी संबंध समूह की बैठक में भारत के विकास सहयोग पर ब्रीफिंग पर एक प्रस्तुति दी।
- 22 नवंबर, 2021 को जेट्रो बैंकॉक और ईआरआईए इंडोनेशिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रिसर्च इंस्टीट्यूट नेटवर्क (आरआईएन) की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित किया।
- 20 नवंबर 2021, नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा संवाद, दिल्ली जिमखाना क्लब द्वारा आयोजित 'क्वाडः वैश्विक और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 17 नवंबर, 2021 को नीति आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख थिंक टैंकों की बैठक में 'भारत–चीन व्यापार घाटा और व्यापक व्यापार विवरण' पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 नवंबर 2021 को कोलंबो में यूएन ईएससीएपी द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर आयोजित पांचवें दक्षिण एशिया फोरम में 'क्षेत्रीय सहयोग के लिए बेहतर और त्वरित एसडीजी उपलब्धि प्राथमिकता कार्रवाई' पर एक प्रस्तुति दी।
- 15 नवंबर, 2021 को यूनिसेफ द्वारा आयोजित 'तेजी से बदलती दुनिया में यूनिसेफ – स्थिति और प्रोग्रामिंग के लिए निहितार्थ' पर सत्र में 'दक्षिण एशियाः कोविड–19 दीर्घ संकट' पर एक प्रस्तुति दी।
- 1 नवंबर, 2021 को रोम में द यूरोपियन हाउस – एम्ब्रोसेटी द्व ारा अफ्रीका और मध्य पूर्व पर आयोजित दूसरे यूरोपीय कॉर्पोरेट परिषद के वार्षिक शिखर सम्मेलन में 'चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का भविष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- आयुष मंत्रालय द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को आयोजित आयुर–उद्यमः कार्यक्रम में 'भारत में आयुष क्षेत्र – संभावनाएं और चुनौतियां' पर एक प्रस्तुति दी।
- 27 अक्टूबर 2021 को जनसंख्या और विकास में भागीदार, ढाका द्व ारा आयोजित राष्ट्रीय दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला में 'राष्ट्रीय टास्क फोर्स और एसएससी को आगे बढ़ाने वाले साझेदार संस्थानों की भूमिका' पर सत्र का संचालन किया।
- 26 अक्टूबर, 2021 को एसए बीआरआईसीएस थिंक टैंक, बीआरआईसीएस, जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट और जोहान्सबर्ग इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स और इब्साः हाल के शैक्षणिक मंचों पर विचार के दौरान 'ब्रिक्स और इब्साः एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य' पर प्रस्तुति दी।
- 22 अक्टूबर 2021 को ईजीआरओडब्लू फाउंडेशन द्वारा आयोजित वेबिनार श्रृंखला में 'भारत चीन व्यापार घाटा और व्यापक व्यापार विवरण' पर एक प्रस्तुति दी।
- 13 अक्टूबर 2021 को जीआईएफटी और पटियाला के खालसा कॉलेज

द्वारा आयोजित 'कोविड–19 और कोविड–19 के बाद के विश्व के लिए नवप्रवर्तन प्रणाली की पुनर्कल्पना' पर ग्लोबलिक्स–इंडियालिक्स वेबिनार में तकनीकी सत्र प्प का संचालन किया।

- 12 अक्टूबर, 2021 को कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एग्रीकल्चर, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च नेटवर्क, एकेडमी ऑफ ग्लोबल फूड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज चाइना सेंटर, यूके, नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक द्वारा आयोजित 'वैश्विक गरीबी और ग्रामीण पुनरोद्धारः चुनौतियां और अनुभव' पर वेबिनार में पैनलिस्ट।
- 12 अक्टूबर 2021 को सीआईआई द्वारा आयोजित सीआईआई सीपीएसई प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स फोरम की पहली बैठक में भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 अक्टूबर, 2021 को एक्ज़िम बैंक द्वारा आयोजित भारत – जापान आर्थिक भागीदारीः व्यापार और परे वेबिनार में 'एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर परिप्रेक्ष्य' प्रस्तुति दी।

प्रोफेसर एस.के. मोहंती

- 9 दिसंबर 2020 को आयोजित इंडिया एक्जिम बैंक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड 2020: आईईआरए अवार्ड कमेटी की दूसरी बैठक पर चर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दक्षिणी नीति पर अध्यक्षीय समिति; अर्थशास्त्र, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (एनआरसी) और कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, कोरिया द्वारा नई दक्षिणी नीति प्लसः दृष्टि, प्रगति और भविष्य पर संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और भारत–कोरिया आर्थिक भागीदारी में गतिशीलताः 21वीं सदी के लिए एक मॉडल पर एक प्रस्तुति दी।
- 1 दिसंबर, 2021 को बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर सीपीडी बांग्लादेश में संयुक्त रूप से आयोजित बैठक 'बांग्लादेश–भारत साझेदारी के 50 वर्षः अगले 50 वर्षों की यात्रा की ओर' में भाग लिया, और 'आधी सदी पुराने भारत–बांग्लादेश व्यापार की एक कहानी', पर आभासी रूप से एक प्रस्तुति दी।
- दिनांक 17 नवंबर 2021 को नीति आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित थिंक टैंक चर्चा बैठक में अध्यक्ष के रूप में भाग लिया।
- उभरते क्षेत्रीय क्रम में भारत–कोरिया संबंधों की पुनर्कल्पनाः 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'न्यू सदर्न पॉलिसी' का तालमेल पर 27 अक्टूबर, 2021 को आरआईएस, आईसीडब्ल्यूए, कोरियाई राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी (केएनडीए) और कोरिया गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति का कोरिया संस्थान (केआईईपी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहले भारत–कोरिया 2+2 द्विपक्षीय वार्ता में एक वक्ता के रूप में भाग लिया और 'कोविड के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारत–कोरिया आर्थिक साझेदारी को फिर से प्रासंगिक बनाना' पर सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 27 अक्टूबर, 2021 को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव पर चर्चा बैठक में भाग लिया।
- 7 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित व्यापार चर्चा बैठक में भाग लिया।

डॉ सब्यसाची साहा

एसोसिएट प्रोफेसर

- एसडीपीआई द्वारा 8 दिसंबर 2021 को आयोजित 24वें सतत विकास सम्मेलन (एसडीसी) के दौरान 'दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर प्रगति पर कोविड–19 का प्रभावः क्षेत्रीय सहयोग के लिए चुनौतियां और आगे की राह' शीर्षक वाले पैनल में पैनलिस्ट (आभासी रूप से भाग लिया)।
- 7 दिसंबर 2021 को ट्यूरिन में आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'ब्रिक्स और औपचारिकताः आईएलओ भागीदार परिप्रेक्ष्य' पर वेबिनार में रिसोर्स पर्सन (आभासी रूप से भाग लिया)।
- 1 दिसंबर, 2021 को जी20 – टीआईआरएन (व्यापार और निवेश अनुसंधान नेटवर्क) द्वारा आयोजित 'सतत विकास उद्देश्यों के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों को बनाए रखने और सुधारने में जी20 की भूमिका' शीर्षक वाले पैनल में पैनलिस्ट (आभासी रूप से भाग लिया)।
- 29 नवंबर से 3 दिसंबर, 2021 तक वी ब्रिक्स इंटरनेशनल स्कूल, मॉस्को, रूस में रिसोर्स पर्सन (आभासी रूप से भाग लिया)।

- 24 से 25 नवंबर, 2021 तक काहिरा, मिस्र में आयोजित 'दक्षिणीय सहयोग पर उच्च स्तरीय एपीआरएम सहकर्मी समीक्षा मंच: अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण में चुस्ती और लचीलापन' में पैनलिस्ट। (आभासी रूप से भाग लिया)।

डॉ प्रियदर्शी दाश

एसोसिएट प्रोफेसर

- 25–27 दिसंबर, 2021 को भोपाल में आयोजित भारतीय आर्थिक संघ के 104वें वार्षिक सम्मेलन में 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश: उभरती गतिशीलता' पर तकनीकी सत्र में प्रस्तुति दी।
- 9 दिसंबर, 2021 को आरआईएस और ओस्लो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'महामारी के बाद की दुनिया में भारत–अफ्रीका संबंधों पर गोलमेज सम्मेलन' में फिनटेक पर प्रस्तुति दी।
- एशिया अफ्रीका फोरम ऑन करप्शन, इंडोनेशिया द्वारा 7–8 दिसंबर, 2021 को एशिया अफ्रीका फोरम समिट ऑन करप्शन 2021 में 'लाभ स्थानांतरण, आर्थिक भगोड़ों और अवैध वित्तीय प्रवाह के संसाधन निहितार्थ' पर एक प्रस्तुति दी।
- 26–27 नवंबर, 2021 को सोका विश्वविद्यालय, जापान द्वारा दक्षिण एशिया में स्मृति और अतीत पर आयोजित दूसरे दक्षिण एशिया अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'हिंद–प्रशांत आर्थिक विजन: भविष्य की एशियाई विकास गाथा में भारत की बड़ी भूमिका' पर प्रस्तुति दी।
- 26–27 नवंबर, 2021 को आरआईएस, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित 'ब्रिक्स आभासी आर्थिक कॉन्क्लेव: वैश्विक आर्थिक सहयोग और ब्रिक्स की भूमिका को फिर से आकार देना – सहक्रियाओं और पूरकताओं की खोज करना' पर वेबिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 24 नवंबर, 2021 को आरआईएस और जी20 रिसर्च फोरम द्वारा आयोजित 'आगामी जी20 की विकासशील देशों द्वारा अध्यक्षता के लिए टी20 सुधार' पर वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र का संचालन किया।
- 28 अक्टूबर, 2021 को आरआईएस और आईएफपीआरआई द्वारा आयोजित 'बिम्सटेक क्षेत्र में संधारणीय कृषि और मूल्य संवर्धन में सहयोग की खोज' पर वेबिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 27 अक्टूबर 2021 को आरआईएस, आईसीडब्लूए, केएनडीए और केआईईपी द्वारा आयोजित 'उभरती क्षेत्रीय व्यवस्था में भारत–कोरिया संबंधों की पुनर्कल्पना: 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'न्यू सदर्न पॉलिसी' का तालमेल पर भारत–कोरिया 2+2 द्विपक्षीय वार्ता में "कोविड के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारत–कोरिया आर्थिक साझेदारी को फिर से प्रासंगिक बनाना" पर तकनीकी सत्र में बतौर परिचर्चा प्रस्तुत किया।
- 8 अक्टूबर 2021 को एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित 'भारत–जापान आर्थिक साझेदारी: व्यापार और उससे परे' में एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर प्रस्तुति दी।

श्री राजीव खेर

विशिष्ठ फैलो

- 18 अक्टूबर, 12 नवंबर और 27 दिसंबर 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अनुशासनात्मक समिति – बेंच– II बैठक में भाग लिया।
- 17 दिसंबर 2021 को आईसीआरआईईआर द्वारा आयोजित वेबिनार 'क्या वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है? हाल के जी20 शिखर सम्मेलन, सीओपी26 और व्यापार चर्चा से कुछ विचार' में हिस्सा लिया।
- 16 दिसंबर 2021 को सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र द्वारा आयोजित "अनशैकलिंग इंडिया: हार्ड ट्रुथ्स एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल" पुस्तक के विमोचन में भाग लिया।
- 13–15 दिसंबर 2021 को सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2022 में भाग लिया।
- 10 दिसंबर 2021 को एसआईएएम द्वारा आयोजित 'विजन सस्टेनेबल मोबिलिटी: सीओपी26 के निहितार्थ' पर व्याख्यान श्रृंखला में भाग लिया।
- 9 दिसंबर 2021 को सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) द्वारा आयोजित 'बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की भूमिका का पुनरीक्षण' पर प्रमुख संगोष्ठी में भाग लिया।
- 3 दिसंबर 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 'बदलते वैश्विक भू–राजनीतिक आयाम और भारत पर इसका प्रभाव' पर यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक इयान ब्रेमर के साथ बातचीत में भाग लिया।

- 2 दिसंबर 2021 को ट्रू नॉर्थ की 17वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।
- गुडइयर इंडिया लिमिटेड द्वारा 11 और 24 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 23 नवंबर 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 'भारत – ताइवान व्यापार सहयोग – सहक्रियाओं के निर्माण और नई भागीदारी' पर डिजिटल सम्मेलन और प्रदर्शनी में भाग लिया।
- सीयूटीएस–सीआईआरसी द्वारा 6 – 17 नवंबर 2021 को आयोजित 'प्रतियोगिता, विनियमन और विकास' सम्मेलन में भाग लिया।
- 29 अक्टूबर 2021 और 10 नवंबर 2021 को किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड द्वारा आयोजित बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 22 अक्टूबर 2021 और 8–9 नवंबर 2021 को एयरटेल बैंक की बोर्ड बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 8 नवंबर 2021 को कोनराड एडीनौर–स्टिफटंग के भारत कार्यालय के सहयोग से आईसीआरआईईआर द्वारा आयोजित 'डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलनः अपेक्षित परिणाम और आगे की राह' पर वेबिनार में भाग लिया।
- 2 नवंबर 2021 को चीन पर सीआईआई कोर ग्रुप की बैठक में भाग लिया।
- सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित 'वन से जुड़ी वस्तुओं के लिए उत्पादन और व्यापार नीतियों में स्थिरता का एकीकरण' पर एक सत्र में भाग लिया।
- 27 अक्टूबर 2021 को मुंबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और अटलांटिक परिषद के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 'सीओपी26 से क्या अपेक्षाएं हैं – भारतीय व्यवसायों के लिए एक रूपरेखा' पर एक विशेष चर्चा में भाग लिया।
- 27 अक्टूबर 2021 को सूर्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्यात पर फोकस' पर चर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल ट्रेड (सीआरआईटी) द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को आयोजित 'संस्थागत मुद्दों और विश्व व्यापार संगठन सुधार' पर विचार–मंथन में भाग लिया।
- 21 अक्टूबर 2021 को अनंत केंद्र के सहयोग से अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली और चेन्नई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावासों के साथ मुंबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित 'नवीकरणीय ऊर्जा के साथ हरित अर्थव्यवस्था का विकास' पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
- सिगुर सेंटर फॉर एशियन स्टडीज और इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को आयोजित 'महामारी के बाद की दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था' पर वेबिनार में भाग लिया।
- आईसीआरआईईआर द्वारा 6–8 अक्टूबर 2021 को आयोजित 'महामारी के युग में वैश्विक आर्थिक समन्वयः जी–20 सदस्यों के विचार' पर 13वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय जी–20 सम्मेलन में भाग लिया।

डॉ पी के आनंद

विजिटिंग फैलो

- 'क्या वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है? हाल के जी20 शिखर सम्मेलन, सीओपी26 और व्यापार चर्चा से कुछ विचार' पर 17 दिसंबर, 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद के कार्यक्रम (आभासी) में हिस्सा लिया।
- 15–16 दिसंबर 2021 को आयोजित '16वें राष्ट्रीय सम्मेलन लक्ष्य 2030 एसेस, एक्ट, एक्सलरेट' पर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया (यूएन जीसीएनआई) के कार्यक्रम (आभासी) में भाग लिया।
- 14 दिसंबर, 2021 को 'भारत–वियतनाम सत्रः व्यापार सहयोग के अवसर' पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया (आभासी)।
- 8 दिसंबर 2021 को आयोजित 'सामाजिक उद्यम और विकलांगताः आसियान क्षेत्र में नवाचार, जागरूकता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा' पर आर्थिक अनुसंधान संस्थान आसियान और पूर्वी एशिया के कार्यक्रम में भाग लिया। (आभासी)
- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आधिकारिक पक्ष कार्यक्रम 'विकास के लिए

पोषण शिखर सम्मेलन 2021: स्वस्थ भविष्य के लिए हर बच्चे को सशक्त बनाना – स्कूल में भोजन और पोषण शिक्षा की संभाव्यता' में भाग लिया, जो 2 दिसंबर, 2021 को आयोजित किया गया था। (आभासी)

- 30 नवंबर 2021 को आयोजित टी20 हैंडओवर कार्यक्रम 'इटली से इंडोनेशिया तक: जी20 रिकवरी पहल में टी20 का योगदान' में भाग लिया। (आभासी)
- 'अफ्रीका और भारत: खाद्य और कृषि में परिवर्तन के साथ अनुभव और सीखने और सहयोग के अवसर' पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, अफ्रीका में कृषि अनुसंधान मंच और बॉन विश्वविद्यालय के विकास अनुसंधान केंद्र द्वारा 26 नवंबर 2021 को संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। (आभासी)
- 24 नवंबर, 2021 को विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत की औद्योगीकरण चुनौतियां, अवसर और आगे की राह पर आयोजित औद्योगिक विकास और भारत भूमि और विकास अध्ययन संस्थान के सम्मेलन में हिस्सा लिया। (आभासी)
- 26–28 अक्टूबर, 2021 के दौरान आयोजित 'इन्वेस्ट इन ह्यूमैनिटी' विषय पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट, एफआईआई रियाद, सऊदी अरब द्वारा आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 5वीं वर्षगांठ पर वेबिनार में भाग लिया।
- इस्टिटूटो अफ़ारी इंटरनेशनल, रोमा ऑफ़ टी20: इटालियन प्रेसीडेंसी द्वारा 11 अक्टूबर, 2021 को 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ईएसजी ढांचे की दिशा में जी20 की भूमिका' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

श्री के कृष्ण कुमार

विजिटिंग फैलो

- 'क्या वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है? हाल के जी20 शिखर सम्मेलन, सीओपी 26 और व्यापार चर्चा से कुछ विचार' पर 17 दिसंबर, 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद के कार्यक्रम (आभासी) में हिस्सा लिया।
- 15–16 दिसंबर 2021 को आयोजित '16वें राष्ट्रीय सम्मेलन लक्ष्य 2030 एसेस, एक्ट, एक्सलरेट' पर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के कार्यक्रम (आभासी) में भाग लिया।
- 14 दिसंबर, 2021 को 'भारत–वियतनाम सत्र: व्यापार सहयोग के अवसर' पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया (आभासी)।
- 8 दिसंबर 2021 को आयोजित 'सामाजिक उद्यम और विकलांगता: आसियान क्षेत्र में नवाचार, जागरूकता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा' पर आर्थिक अनुसंधान संस्थान आसियान और पूर्वी एशिया के कार्यक्रम में भाग लिया। (आभासी)
- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आधिकारिक पक्ष कार्यक्रम 'विकास के लिए पोषण शिखर सम्मेलन 2021: स्वस्थ भविष्य के लिए हर बच्चे को सशक्त बनाना – स्कूल में भोजन और पोषण शिक्षा की संभाव्यता' में भाग लिया, जो 2 दिसंबर, 2021 को आयोजित किया गया था। (आभासी)
- 30 नवंबर 2021 को आयोजित टी20 हैंडओवर कार्यक्रम 'इटली से इंडोनेशिया तक: जी20 रिकवरी पहल में टी20 का योगदान' में भाग लिया। (आभासी)
- 'अफ्रीका और भारत: खाद्य और कृषि में परिवर्तन के साथ अनुभव और सीखने और सहयोग के अवसर' पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, अफ्रीका में कृषि अनुसंधान मंच और बॉन विश्वविद्यालय के विकास अनुसंधान केंद्र द्वारा 26 नवंबर 2021 को संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। (आभासी)
- 24 नवंबर, 2021 को विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत की औद्योगीकरण चुनौतियां, अवसर और आगे की राह पर आयोजित औद्योगिक विकास और भारत भूमि और विकास अध्ययन संस्थान के सम्मेलन में हिस्सा लिया। (आभासी)
- 26–28 अक्टूबर, 2021 के दौरान आयोजित 'इन्वेस्ट इन ह्यूमैनिटी' विषय पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट, एफआईआई रियाद, सऊदी अरब द्वारा आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 5वीं वर्षगांठ पर वेबिनार में भाग लिया।
- इस्टिटूटो अफ़ारी इंटरनेशनल, रोमा ऑफ़ टी20: इटालियन प्रेसीडेंसी द्वारा 11 अक्टूबर, 2021 को 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ईएसजी ढांचे की दिशा में जी20 की भूमिका' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

माननीया विदेश राज्य मंत्री ने आरआईएस के कार्यक्रम की सराहना की....

...शेष पृष्ठ 1 से जारी

स्तंभों, साझेदारी मंचों, वैश्विक नेटवर्क, प्रकाशन और क्षमता निर्माण संबंधित कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संकाय के सदस्यों ने माननीया मंत्री को अपने कार्यक्षेत्रों के बारे में अवगत किया जिनमें प्रमुख हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार; लैटिन अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक संबंध; नियम–आधारित भारत–प्रशांत, भारत–यूरोपीय संघ संयोजकता साझेदारी और विकास; हिंद महासागर में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनायें; संयुक्त राष्ट्र एसडीजी के संदर्भ में; दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग; विज्ञान नीति और विज्ञान राजनय तथा क्षेत्रीय विकास के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच साझेदारी आदि। माननीय मंत्री ने सभी संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की और विकासशील देशों के विचार–मंडल के रूप में कार्य करने की दिशा में उपरोक्त क्षेत्रों में आरआईएस के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी संकाय सदस्यों को साक्ष्य–आधारित और

नीति–प्रासंगिक अनुसंधान में संलग्न होने, कठोर विश्लेषण करने और इनमें राष्ट्रीय हित को जोड़ने के साथ–साथ सामूहिक बौद्धिक प्रयासों में भारतीय विचार और संस्कृति को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ■

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर IV-B, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत। दूरभाष 91–11–24682177–80
फैक्स: 91–11–24682173–74, ईमेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: www.ris.org.in

हमें यहां फॉलो करें:
www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi